01/2014

स्प्रू हाउस पत्र

संक्रमण, क्षेत्रीय एकीकरण और जटिलताएं : विकसित होते भारत-अफगानिस्तान पारस्परिक संबंध

दिनोज के उपाध्याय और अथर जाफर

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
स्प्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001

संक्रमण, क्षेत्रीय एकीकरण और जटिलताएं : विकसित होते भारत-अफगानिस्तान पारस्परिक संबंध

दिनोज के उपाध्याय और अथर जाफर

संक्रमण, क्षेत्रीय एकीकरण और जटिलताएं : विकसित होते भारत-अफगानिस्तान पारस्परिक संबंध

प्रथम प्रकाशन, 2014

प्रतिलिप्याधिकार © विश्व मामलों की भारतीय परिषद

आईएसबीएन: 978-93-83445-06-6

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रकाशन का कोई भी भाग कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, उद्धृत, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहित या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग से या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेष रूप से लेखक की है और उसकी व्याख्या, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद,
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली -110 001, भारत
दूरभाष। : + 91-11-23317242, फैक्स: + 91-11-23322710
www.icwa.in

मुद्रक:
एल्फा ग्राफ़िक्स
6A/1, गंगा चैम्बर्स, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग,
नई दिल्ली - 110005 दूरभाष : 9312430311
ई-मेल : tarunberi2000@gmail.com

विषय - सूची

प्रस्तावना

राजनीतिक संक्रमण

मंद लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया

सुरक्षा संक्रमण और नशीले पदार्थों का प्रकोप

आर्थिक संक्रमण और विकास

अर्थव्यवस्था का पुनर्रूद्धार करने के प्रति काबल की नीतिगत प्रक्रिया

अफगानिस्तान के साथ भारत के विकसित होते पारस्परिक संबंध

अफगानिस्तान में बहुपक्षीय प्रक्रियाओं में भारत की सहभागिता

अफगानिस्तान : उभरती क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता का केन्द्र

संक्रमण, क्षेत्रीय एकीकरण और जटिलताएं : विकसित होते भारत-अफगानिस्तान पारस्परिक संबंध

सार: 2014 में राजनीतिक और सुरक्षा संक्रमण अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा ये उसके पड़ोसी देशों पर प्रभाव डालेंगे। दक्षिण एशिया में सुरक्षा के एक प्रमुख हितधारक के रूप में, अफगानिस्तान में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका युद्ध से जीर्ण-शीर्ण इस देश की स्थिरता और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के साथ भारत का निरंतर चलता आ रहा संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि देश में संक्रमण और सांमजस्य की प्रक्रिया किस प्रकार प्रारंभ होती है। हालांकि, सुरक्षा और रणनीतिक चिंतन अफगानिस्तान के भावी मार्ग पर निरंतर अपना अधिपत्य जमाए हुए है, देश के प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों की हालिया खोज तथा माल और ऊर्जा में प्रादेशिक व्यापार के लिए एक केन्द्र के रूप में उभरने की इसकी क्षमता ने क्षेत्रीय देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों के मध्य सहयोग के नए आयाम खोल दिए हैं।

मुख्य शब्द : सुरक्षा-राजनीतिक संक्रमण, सामंजस्य प्रक्रिया, सॉफ्ट पावर उपाय, प्रादेशिक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा।

प्रस्तावना

अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बलों द्वारा हासिल की गई सीमित सफलता ने इस समीकरण को पुन: प्रवर्तित कर दिया है बाहय सैन्य हस्तक्षेप किसी देश में स्थायी शांति प्रभावी सुरक्षा और टिकाऊ स्थायित्व लाने में प्राय: विफल हो जाते हैं। 11 सितम्बर, 2001 के भयानक आक्रमणों के उपरांत अफगानिस्तान में अमेरिकी-नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप को एक दशक से भी अधिक समय हो चुका है परंतु देश में उभरता हुआ परिदृश्य अभी भी संतोषजनक स्थिति से काफी दूर है। अफगानिस्तान में समग्र संक्रमण प्रक्रिया जटिल और दीर्घकालिक प्रतीत होती है : देश को अभी तक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थायित्व का सामना करना है। अफगानिस्तान सैन्य घुसपैठ, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक भंगुरता, आर्थिक अनिश्चितता, नृजातीय प्रतिद्वंद्विता और निरंतर चल रही बाहरी सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेपों के प्रति काफी कमजोर रहा है। एक दशक लंबे उग्रवाद-विरोधी उपायों के बावजूद तालीबान निरंतर अपना सुदृढ़ राजनीतिक और सुरक्षा उपस्थिति को बनाए रखने में सफल रहा है, संभवत: उसने देश के संपूर्ण भू-भाग पर अपनी कार्यवाहियों के क्षेत्रों को विस्तारित किया है।[1] अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की क्षमताएं तथा इसका वैविध्यपूर्व प्रशिक्षित नेतृत्व इस समय परीक्षा की घड़ी के अंतर्गत आएगा जब वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सहायता बलों (आईएसएएफ) से 2014 में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा अनुरक्षित करने का पूर्ण प्रभार हासिल कर लेंगे।

अफगानिस्तान का दोहरा संक्रमण-राजनीतिक और सुरक्षा-इसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद कर्जई ने 2014 में अपने पद पर दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, जो अफगानिस्तान के वर्तमान संविधान के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम कार्यकाल हैं। नए राष्ट्रपति का

निर्वाचन करने की प्रक्रिया विवादपूर्ण थी तथा इसमें कुछ समय का विलंब हो गया था। देश के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग द्वारा 14 जून 2014 को तब पुनः परीक्षण संचालित किया जब 5 अप्रैल, 2014 को आयोजित चुनावों के प्रथम चक्र में कोई भी उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक मत प्रापत करने में सफल नहीं हुआ। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में डा. अशरफ घानी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डा. अब्दुल्ला अब्दुल्ला के नेतृत्व में, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष ही नया तैयार किया गया पद था[2], नई गठबंधन सरकार दो पूर्व प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर निर्मित की गई है, के बारे में संशयवादी इस सहमति की व्यवहार्यरता और सरकार के जारी रहने के संबंध में संदेह व्यक्त किया है। राजनीतिक नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर निरंतर बनी हुई अनिश्चितता न केवल शासन संबंधी संकट उत्पन्न कर सकती है बल्कि नृजातीय मोर्चे पर भी अनवरत गुटबंधी का कारण बन सकती है।

दूसरी ओर, देश की शांति और स्थायित्व के लिए निर्णायक समझी गई समाधान प्रक्रिया अपनी प्रारंभिक अवस्था पर है तथा अभी तक यह दुर्ग्राह्य रही है। इस प्रक्रिया की एक प्रमुख कमी यह है कि यह अफगान द्वारा प्रारंभ की गई, अफगानी नेतृत्व वाली अथवा अफगान के नियंत्रण वाली नहीं है। अमेरिका द्वारा समर्थित वार्ताओं का अंतिम चक्र अफगान पक्षों के बीच राजनीतिक वैधता के मुद्दे पर अचानक ही समाप्त हो गया।[3] तथापि, कतर ने अमेरिका और तालीबान के बीच युद्ध के बंदियों के प्रथम आदान-प्रदान को सुकर बनाया। सार्जेंट बोव बर्गदाल्ह तालीबान द्वारा बंदी बनाया गया था जिसे ग्वाटानामो खाड़ी में अमेरिका द्वारा पकड़े गए तालीबान के पांच वरिष्ठ बंदियों की रिहाई के एवज में रिहा किया गया। हालांकि कर्जई प्रशासन, जिसे अमेरिका द्वारा इस सौदे के बारे में सूचित नहीं किया गया था, इसकी आलोचना की थी, कुछ विश्लेषकों का मत था कि यह आदान-प्रदान तालीबान तथा अफगान सरकार के बीच समाधान प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने में सहायता कर सकता है।

2014 के उपरांत के परिदृश्य में, टिकाऊ राजनीतिक स्थायित्व अनवरत शांति तथा अंतर्वेशी आर्थिक विकास के लिए अफगानिस्तान अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और सहायता हासिल करने की आशा कर रहा है जिसमें इसके पड़ोसी देश जैसे भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई राज्य भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की सुरक्षा और विकास में प्रमुख हितधारक होने के नाते भारत काबुल में होने वाले घटनाक्रम पर अत्यंत उत्सुकता के साथ नज़र रखे हुए हैं तथा वह प्रादेशिक राजधानियों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए एक चुनोती के रूप में अफगानिस्तान में अस्थिरता, निरंतर चल रही राजनीतिक अस्त-व्यवस्तता और वहां तालीबान के संभावित उदय की गंभीर विवक्षाओं तथा व्यापक आथ्रिक हितों और संभावित ऊर्जा मार्ग पर विचार करते हुए भारत की चिंताएं सही प्रतीत होती हैं। राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी कारणों के अलावा भारत की अफगानिस्तान में पर्याप्त आर्थिक साझेदारी भी निहित है। अपनी भू-रणनीतिक अवस्थिति के कारण अफगानिस्तान बेहतर आर्थिक एकीकरण की भारत की आकांक्षा के लिए विशेष रूप से ऊर्जा और खनिज संसाधनों तथा मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है। हालांकि नई दिल्ली दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच

क्षेत्रीय स्थायित्व तथा अधिक आर्थिक एकीकरण हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में सॉफ्ट पावर उपायों को मुख्य रूप से क्रियान्वित करने के प्रति इच्छुक बना हुआ है, अफगानिस्तान से इस संबंध में मांग उठती रहती है कि भारत काबुल के साथ् अपने रक्षा सहयोग को व्यापक बनाए।

पश्चिम और पूर्व में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ईरान और चीन ने भी अपनी सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं के मद्देनजर इस देश के घटनाक्रमों पर अपनी नज़र बनाई हुई है। ईरान एक प्रमुख पारेषण मार्ग तथा अवैध अफगानी नशीले पदार्थों के लिए एक बाजार है, तथापि, इसके स्वापक पदार्थ-विरोधी उपाय इस संकट को नियंत्रित करने में काफी प्रभावशाली रहे हैं। तेहरान में नशीले पदार्थों के विरुद्ध कड़े कानून हैं, जिन्हें कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है। 2013 में, अक्तूबर तक 500 से अधिक लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था।[4] मृत्युदण्ड पाने वाले लोगों में से लगभग तीन-चौथाई लोग नशीले पदार्थों के आरोप में दोषी पाए गए थे[5] जिनमें अफगानी लोग समस्त मृत्युदण्ड पाने वालों में से पर्याप्त संख्या में भी। देश में अफगान शरणार्थियों की एक विशाल संख्या, जिसकी जड़ अफगानिस्तान में अस्थिरता में निहित है, ईरान द्वारा सामना किया जाने वाला एक अन्य मुद्दा है जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रहा है। दूसरी ओर, चीन अपने पश्चिमी जिनजियान क्षेत्र में अलगाववादी प्रवृत्तियों से जूझ रहा है जिसके साथ अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणतंत्रों की सीमाएं लगती हैं। बीजिंग के थियनानमेन स्क्वायर में हालिया हिंसा की घटना तथा प्रादेशिक राजधानी उरुमक्वी में बमबारी का दोष प्राधिकारियों द्वारा उइघुर अलगाववादियों के सिर मढा गया है, जो अस्थिर अफगानिस्तान को अलगाववादियों के लिए एक आसानी से सुलभ अभ्यारण्य मानते हैं। चीन भी आर्थिक उपायों द्वारा अफगानिस्तान के मुद्दे का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। देश अफगानिस्तान में अवसंरना का विकास करने के लिए पर्याप्त निवेश कर रहा है जिसमें चीन के औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों के साथ देश की खानों को जोड़ने वाली आर्थिक रेल-लाइन[6] भी शामिल है।

इन महत्वपूर्ण घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह पत्र अफगानिस्तान और उसके पड़ोस में विद्यमान स्थिति का विश्लेषण करता है और साथ ही वर्ष 2001 से अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा भारत-मध्य एशिया व्यापार के लिए विशेष रूप से खनिज और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में संभावनाओं में काबुल की भूमिका की समीक्षा भी करता है।

राजनीतिक संक्रमण

हालांकि हामिद कर्जई ने 2001 में तालीबान सरकार के पतन के बाद से अफगानिस्तान पर शासन किया था तथा उसने केन्द्र में एक स्थिर नेतृत्व प्रदान किया था, राजनीतिक चुनौतियां अभी भी विद्यमान थीं तथा काबुल में नए नेतृत्व की अभी परीक्षा की जानी बाकी थी। देश की राजनीतिक संस्थाएं अभी भी विकास की अवस्था में थीं तथा कोई एक राजनीतिक दल अथवा सर्व-अफगान अपील के साथ कोई राजनीतिक व्यक्तित्व देश के राजनीतिक क्षितिज पर नहीं उभर पाया था। अधिकांश दल अथवा गठबधन नृजातीय और पंथवादी विचारधाराओं पर आधारित थे अथवा वे सैद्धांतिक विचारों अथवा राष्ट्रीय मुद्दों पर गठित होने के अलावा किसी दल-विशेष के विरोध में था।

राष्ट्रपति चुनाव और उसके उपरांत मतों की परीक्षा के दीर्घकालिक अंतराल के उपरांत एक नई सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के ऐसे अंतरण के उपरांत तालीबान के निरंतर विरोध के मध्य 29 सितम्बर, 2014 को अपना कार्यभारत संभाला। राजनीतिक आकस्मिकताओं ने दोनों प्रतिद्वंद्वियों से यह अपेक्षा की कि वे शांति और राजनीतिक स्थायित्व के लिए एक साथ हो जाएं। तथापि, आंतरिक और बाह्य गतिशीलताओं को प्रंबधित करना नई सरकार के लिए एक चुनौती बना रहा। आंतरिक दृष्टि से, तालीबान सरकार का विरोध कर रहा है तथा संयुक्त राष्ट्र के साथ सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरे, नेताओं को अपने निर्वाचकों को यह आश्वासन देने की आवश्यकता थी कि एकता का सौदा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध नहीं है क्योंकि निर्वाचकों को या तो घानी अथवा अब्दुल्ला को मत देना होगा न कि घानी और अब्दुल्ला को जैसा कि एकतापूर्ण सरकार प्रतिनिधित्व करती है। बाह्य दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेष रूप से अमेरिका और संयुक्त मतभेदों को समाप्त करने के लिए सहमत किया ताकि एक नई सरकार का गठन किया जा सके। गठबंधन सरकार उग्रवाद का सामना करने, राज्य-निर्माण प्रक्रियाओं को सुकर बनाने, अंतर्वेशी विकास को प्रोत्साहित करने तथा प्रांतीय स्तर पर सुचारू सुरक्षा और राजनीतिक रूपांतरण प्रभारी करने के लिए बाहरी और आंतरिक जटिलताओं के उठने वाले भारी दबाव में होगी।[7] गठबंधन सरकार में विद्यमान नैसर्गिक विरोधाभासों द्वारा इसकी कार्यकुशलता और सुचारू कार्यकरण, विशेष रूप से प्रमुख पदों की नियुक्ति की प्रक्रियाएं प्रभावित होने की संभावना है।

अफगानिस्तान में समझौते की प्रक्रिया कुछ समय से चल रही थी। इसमें अफगान कार्यकर्ता, क्षेत्रीय व्यक्तित्व तथा अमेरिका शामिल है जो इस प्रक्रिया के प्रमुख सहयोगकर्ता रहे हैं। समझौता प्रक्रिया का भाग्य अफगानिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी रूपांतरण दोनों ही के लिए तथा क्षेत्र में स्थायित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि कर्जई प्रशासन तथा तालीबान के बीच वार्ताओं के अनेक चक्र कतर में आयोजित किए जा चुके हैं, इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। समस्त वार्ताएं रहस्यमयी बनी हुई हैं तथा असंतोष के स्वर गहराते जा रहे हैं। प्रमुख हितधारकों के मध्य विभेद अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं, शक्ति विभाजन व्यवस्था, सरकार में नृजातीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों विशेष रूप से बालिकाओं और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के मुद्दे पर बना हुआ है। समझौता वार्ताएं अब एक नए स्थान अर्थात् यूएई की ओर स्थानांतरित हो गई है तथा यह आशा की जाती है कि समझौता वार्ताओं के आबू धाबी चक्र में कोई न कोई परिणाम अवश्य ही निकलेगा।[8] अपने पद पर आसीन होने के प्रथम सप्ताह में ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने तालीबान से शांति प्रक्रिया में शामिल होने का अनुरोध किया था।[9] तथापि तालीबान ने अपना आक्रामक रुख जारी रखा और समझौता प्रक्रिया को पुन: प्रारंभ करने के लिए उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने वार्ताओं के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया[10] तथा राष्ट्रीय गठबंधन सरकार को अमेरिका द्वारा प्रतिस्थापित 'दिखावा' बताया।[11]

धीमा लोकतांत्रीकरण प्रक्रिया

अफगानिस्तान में एक अंतर्वेशी, भागीदारी और लोकतांत्रिक राज्य-संरचना की स्थापना करने के लिए एक साकल्यवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा संविधान भी समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को निर्धारित करता है। तथापि, लोकतांत्रिक लोकाचार और मूल्यों की पाश्चात्य अवधारणा पर आधारित विदेशी संस्थाएं अफगान राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदण्डों और मूल्यों के समरूप प्रतीत नहीं होती जिन्हें ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित किया गया है। आंतरिक लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित करने के स्थान पर उदारवादी लोकतंत्र की परिकल्पना अफगानिस्तान को निर्यातित कर दी गई है तथा इसके क्रियान्वयन में एक ऊर्ध्वमुखी पद्धति अपनाई गई है जिसे आधुनिक शासन प्रणाली के अपेक्षित उद्देश्यों के लिए आम अफगान लोगों द्वारा अभी आत्मसात किया जाना शेष है। प्रादेशिक तथा नृजातीय निष्ठाओं को सर्व-अफगान राष्ट्रीय पहचान में समावेशित किया जाना अभी शेष है। सामाजिक चुनौतियां अभी भी विद्यमान है तथा सशस्त्र सेनाओं सहित शासन की संस्थाओं में नृजातीय और धार्मिक त्रुटियां दृश्यमान होती है।[12] इसी प्रकार, राजनीतिक दलों का भी नृजातीय-धार्मिक हितों से जुड़ा पर्याप्त सहयोग आधार प्राप्त है।[13]

अफगानिस्तान में विद्यमान राष्ट्रीय गठबंधन सरकार ने एक सर्व-अफगान राष्ट्रीय पहचान विकसित करने की आशा बलवती की है। शीर्ष स्तर पर विभिन्न पृष्ठभूमियों के दो राजनीतिक नेताओं के बीच विद्यमान राजनीतिक तंत्र देश को ऐसी शासन प्रणाली और संस्थाएं विकसित करने का राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराता है जिसमें अफगान जनसंख्या के विभिन्न वर्ग समाति हैं तथा यह सर्व-अफगान राष्ट्रीय पहचान सृजित करने में सहायता करता है।

सुरक्षा संक्रमण और नशीले पदार्थों का प्रकोप

आईएसएफ बिना किसी प्रभावी और दक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण की स्थापना किए अथवा उग्रवादी और आतंकवाद की चुनौतियों का उन्मूलन किए अफगानिस्तान से वापस कर रही है। हालांकि अफगान राष्ट्रीय बलों ने लगभग समस्त देश की सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया है, राजधानी सहित विभिन्न स्थानों पर हिंसक और जटिल प्रकृति के हमले अभी भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय बलों की वास्तविक शक्ति और पेशेवर प्रकृति की उस समय परीक्षा होनी बाकी है, जब अंतर्राष्ट्रीय बल पूरी तरह से वापस चले जाएंगे अथवा राष्ट्रीय बलों की सहायता करने में केवल एक सीमित भूमिका ही निभाएंगे, जैसा कि अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित करार में परिकल्पना की गई है।

नई अफगान सरकार ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा करार (बीएसए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बीएएस 9800 अमेरिकी और लगभग 2000 नाटो टुकिड़यों को 2024 तक देश में बने रहने तथा साथ ही अमेरिका की ओर से सतत सैन्य और नागरिक सहायता प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करता है।[14] बीएसए अफगान राष्ट्रीय बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का प्रावधान भी करता है। इस करार के फलस्वरूप अमेरिका-अफगान संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है जो कर्जई के राष्ट्रपति शासन के अंतिम चरण के दौरान कड़ुवाहट से भर गए थे।[15]

अफगान सुरक्षा बलों द्वारा अनेक आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना किया जा रहा है जिनमें से कुछ हैं - उच्च भीतरघात द्वारा हत्याएं, बड़े पैमाने पर प्रवास तथा अवसंरचना और उपकरणों का अभाव।[16] अफगानिस्तान में सुरक्षा अभी भी काफी कमजोर है तथा यह सभी क्षेत्रों में देश के विकास में बाधा बनने के कारण सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक असुरक्षित परिवेश में व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से संचालित नहीं किए जा सकते हैं। तालीबान को ही एकमात्र सुरक्षा चुनौती समझना एक भूल होगी क्योंकि वहां ऐसे अनेक अन्य सशस्त्र समूह भी विद्यमान हैं जो हिंसा, आतंक, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। संगठित समूह मुख्य रूप से अफीम की खेती तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके लाभप्रद व्यापार पर फल-फूल रहे हैं। कथित रूप से, तालीबान अपना राजस्व नशीले पदार्थों, फिरौती और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध उत्खनन द्वारा प्राप्त करता है। अफगानी किसान अफीम की खेती से उन्हें प्राप्त होने वाली आय में से तालीबान को कुछ अंश का भुगतान करने के लिए विवश हैं।

मृदा की संरचना, मौसम की परिस्थितियों, कमजोर विनियामक तंत्र और लाभ हासिल करने वाले हितधारकों के संगठन की संलिप्तता तथा साथ ही आम अफगानियों के लिए वैध और मर्यादित आजीविका अवसरों के अभाव के फलस्वरूप देश विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है।[18] नशीले पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी अफगान अफीम जोखिम आकलन 2013 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि असुरक्षा, कमजोर शासन और कृषि सहायता का अभाव निरंतर होती अफीम की खेती के पीछे मुख्य कारण हैं।[19] निरंतर असुरक्षा, अफीम की पैदावार तथा सशस्त्र संगठनों का यह त्रिकोण एक अत्यंत घृणित दुष्चक्र का निर्माण करता है जिससे असुरक्षा को योगदान मिलता है और अवसरवादी इससे लाभान्वित होते हैं। तथापि, केवल अफगानियों को ही अफीम की पैदावार के लिए दोषी नहीं माना जा सकता है। मांग पक्ष की ओर से देखने पर पश्चिम का विशाल बाजार दिखाई पड़ता है, तथा विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों में स्वापक औषधियों के व्यापार में सरकार अधिकारियों की तथाकथित भागीदारी को अफगानी भूमि से इस चुनौती को कम करने में एक प्रमुख बाधा के रूप में विश्लेषित किया जाना चाहिए।[20]

आर्थिक संक्रमण और विकास

तीन से भी अधिक दशकों की अस्त-व्यस्तता और विवाद ने अफगान अर्थव्यवस्था के विकास को बाधित किया है। तालीबान शासन के अंतर्गत देश के अंतर्राष्ट्रीय पृथक्करण ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों तथा वैश्विक आर्थिक संरचनाओं के साथ इसके संपर्कों को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लंबे समय तक चले युद्धों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका प्रणाली को नष्ट कर दिया तथा निरंतर वैश्वीकृत होते विश्व में व्यापारिक क्रियाकलापों की संभावनाओं को बाधित किया। तालीबान के सत्ता से हटने के उपरांत अफगान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। फिर भी 2004 के बाद से, अफगान की अर्थव्यवस्था ने पर्याप्त प्रगति की। इसमें पिछले दस वर्षों (2003-2012) में 9.2 प्रतिशत की औसत विकास दर से सुधार आया है।[21]

तालिका-1 यह दर्शाती है कि कृषि के अलावा सेवा, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र भी अफगान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश की जीडीपी में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन क्षेत्रों में विकास रोजगार के अवसर सृजित करेगा तथा अफगान अर्थव्यवस्था के आधार पर विविधता प्रदान करेगा।

चित्र 1 . अफगानिस्तान में वार्षिक जीडीपी विकास दर, 2003-13

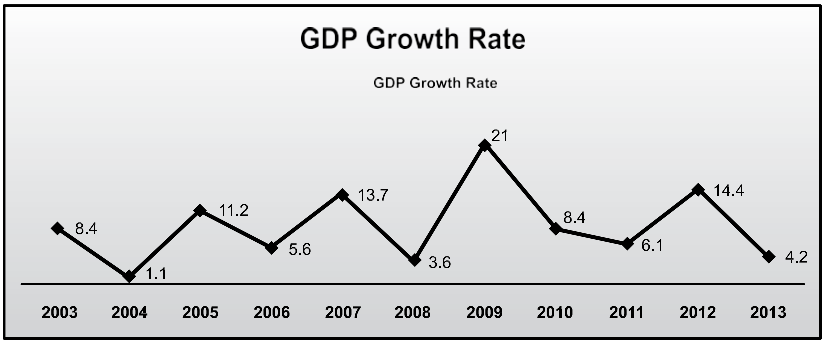

स्रोत : विश्व बैंक [22]

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक पुनर्रूद्धार की सकारात्मक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। तथापि, अफगान अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर और साथ ही देश से विदेशी बलों के वापस चले जाने के उपरांत बनने वाले परिदृश्य में विकास की इस गति को बनाए रखना है। जब 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बल यहां से चले जाएंगे और जब अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मददगार विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्र स्वंय ही वित्तीय संकट से घिरे हैं, काबुल अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन जुटाने की एक विशाल चुनौती का सामना कर रहा है, जो पर्याप्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है।[23] निरंतर अल्प होती अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता का प्रभाव भी पहले से दिखाई देने लगा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को अफगानिस्तान के लिए खाद्य आपूर्ति में कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहातया में कमी होने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।[24]

अंतर्राष्ट्रीय सहायता के अलावा, जो किसी भी देश के लिए सदैव के लिए जारी नहीं रखी जा सकती है अफगानिस्तान को घरेलू संसाधनों से राजस्व जुटाने की भी आवश्यकता है। देश को अवसंरचना का निर्माण करने, अंतर्वेशी आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने तथा गरीबी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। विश्व बैंक के अनुसार, अफगानिस्तान का कर राजस्व संग्रहण 2012 में जीडीपी के 7.5 प्रतिशत की दर पर अपेक्षाकृत निम्न था, जिसमें 2011 में 8.9 प्रतिशत और 2010 में 9.1 प्रतिशत की तुलना में गिरावट आई थी।[25]

तालिका 1 : जीडीपी में क्षेत्रों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कृषि	38.5	36.8	28.5	30.2	27.2	27.3	22.4	27	23.3
खनन	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6
विनिर्माण	18.7	18.1	18.8	17.4	17.1	15.6	15.4	13.5	13
निर्माण	4.8	6	9.4	11.2	13.8	13.2	14	12.5	12.4
अन्य उद्योग	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
सेवाएं	37.8	38.8	43.1	40.9	41.6	43.4	47.6	46.5	50.7

स्रोत : विश्व बैंक 2012, 24[26]

देश में एक कमजोर आर्थिक प्रणाली है तथा इसे सुदृढ़ बनाए जाने और अधिक दक्ष बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि एक गुंजायमान अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यवहार्य आधार स्थापित किया जा सके। अधिकांश अफगान जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है परंतु इसकी कुल भूमि से केवल 12 प्रतिशत ही कृषि योग्य भूमि है और 75 प्रतिशत भूमि रेगिस्तानी है।[27] आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अफगान सरकार ने अनेक पहलें की हैं जिसमें क्षेत्रीय देशों, प्रमुख वैश्विक महाशक्तियों और वैश्विक संस्थाओं से सहायता हासिल करना भी शामिल है।

देश में प्रुचर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है तथा इसमें क्षेत्रीय व्यापार आवागमन गलियारा बनने की पर्याप्त संभावनाएं भी व्याप्त हैं।[28] प्राकृतिक संसाधनों की हाल में की गई खोज सतत् आर्थिक विकास और भावी औद्योगिकीकरण के लिए व्यवहार्य आधार प्रदान करती है। अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान 1 ट्रिलियन[29] यूएस डॉलर से 3 ट्रिलियन[30] यूएस डॉलर तक की परिधि में है तथा इसमें तेल, गैस, तांबे, लोहे और सोने के व्यापक भंडार शामिल हैं। लौह अयस्क का भंडार 421 बिलियन यूएस डॉलर, तांबे का भंडार लगभग 274 बिलियन यूएस डॉलर और सोने का भंडार 25 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का है।[31] इसके अलावा, देश में 36.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस और 3.6 बिलियन बैटल तेल का भण्डार भी है।[32] तालिका 1 दर्शाती है कि खनन क्षेत्र की भागीदारी में अफगान जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, परंतु अभी भी यह एक प्रतिशत से कम है। इसके अलावा, अफगानिस्तान के पास निर्माण और सेवा क्षेत्र में एक व्यापक क्षमता भी है तथा औषधीय प्रयोग के लिए अफीम की पैदावार और उसके प्रसंस्करण की संभावनाएं भी विद्यमान हैं। अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या देश का एक अन्य आर्थिक लाभप्रद पहलू है। अफगानिस्तान की कुल 31 मिलियन जनसंख्या में से लगभग 68 प्रतिशत भाग 25 वर्ष से कम आयु का है।[33] युवा कौशल संवर्धन कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के साथ इन ऊर्जावान युवाओं को लाभकारी मानव संसाधन आधार के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था का पुनरूद्धार करने के प्रति काबुल की नीतिगत प्रतिक्रिया

अफगान सरकार द्वारा संचालित की गई पहलों ने अफगान अर्थव्यवस्था के लिए लाभ प्रदान करने आरंभ कर दिए हैं। काबुल ने देश के खनन और अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों और विनियमों में सुधार किया है। इसने विद्यमान भौतिक अवसंरचना गतिरोधों को समाप्त करने के लिए भी पहलें की हैं। अफगान का संविधान (2004) और अफगान निवेश विधि (2005) विदेशी निवेशकों को उनके निवेशों की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं जिसमें 100 प्रतिशत स्वामित्व और पूंजी और राजस्व के देश-प्रत्यावर्तन पर किसी प्रकार का निर्बंधन शामिल नहीं है।[34] तथापि, अफगानिस्तान को विभिन्न मोर्चों पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। वैमनस्यपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा परिवेश के अलावा देश 'विश्वव्यापी शासन संकेतक रिपोर्ट' में अपनी बात उठाने और उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा की अनुपस्थिति, सरकारी प्रभावकारिता, विनियामक गुणवत्ता, कानून के नियम और भ्रष्टाचार के नियंत्रण जैसे मुद्दों पर अभी भी निम्नतम स्थान पर है।[35] यह पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अवबोधन सूचकांक 2013 में उत्तर कोरिया और सोमालिया के साथ 175वें स्थान पर है।[36] व्यापार करने में आसानी के संबंध में देश की स्थिति अभी भी उचित नहीं है। अफगानिस्तान का व्यापार करने का रैंक 2014 में 189 देशों में से 164 है।[37]

काबुल ने देश में अवसंरचना विकसित करने के लिए अनेक पहलें आरंभ की हैं, जैसे अवसंरचना विकास क्लस्टर के अंतर्गत तैयार किया गया राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संसाधन कॉरीडोर कार्यक्रम (एनआरआरसीपी)।[38] ये कार्यक्रम एकीकृत आर्थिक पहल के रूप में प्रारंभ किए गए हैं जो निष्कर्षित उद्योगों से उच्च निर्यात क्षमता के गलियारों के साथ विद्यमान और योजनाबद्ध अवसंरचना परियोजनाओं को जोड़ते हैं। अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देशों जिसमें ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं के साथ अपने संबंधों का विकास करने का प्रयास भी कर रहा है। एक आधुनिक परिवहन नेटवर्क, जो अफगानिस्तान को उसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है, क्षेत्र में एक दीर्घकालिक विकास उत्पन्न करेगा। वर्ष 2010 में देश ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए जिसने पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान से भारत को माल का प्रेषण सुगम बनेगा। प्रभावी सुरक्षा उपाय, अनुकूल राजनीतिक परिवेश आदि व्यापार करार के संभावित इष्टतमीकरण के लिए अनिवार्य तत्व हैं।

राष्ट्रपति अशरफ घानी, जो एक शिक्षाविद है और जिन्हें विश्व बैंक में सेवा करने तथा बाद में कर्जई प्रशासन के अंतर्गत वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, अफगान की अर्थव्यवस्था का पुनरूद्धार करने के लिए पहल उठा रहे हैं। उन्होंने तत्काल ही भ्रष्टाचार सहित आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों का निवारण करने की ओर भी संकेत किया। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रपति घानी ने 'अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए सुदृढ़ निवेश परिवेश' सृजित करने का आश्वासन दिया है तथा इसे अपनी सरकार की 'प्राथमिकताओं में से एक' बनाया है।[39] उन्होंने सरकार की नीति में अर्थव्यवस्था के महत्व को रेखांकित करने के लिए चीन की प्रथम राजकीय यात्रा की।

अफगानिस्तान के साथ भारत के विकसित होते पारस्परिक संबंध

अंतकाल से ही, भारत के अफगानिस्तान के क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। पाटलीपुत्र के मौर्य साम्राज्य में अफगानिस्तान के क्षेत्र भी शामिल थे जिनमें बाद की अवधि में 'गंधार कला' काफी फली-फूली थी। बौद्ध धर्म अफगानिस्तान आया तथा भारत से मध्य एशिया तक विकसित हुआ। सिल्क रूट के माध्यम से सांस्कृतिक संपर्क और व्यापार संबंधों के ऐतिहासिक अतीत में दोनों देशों को एक-दूसरे के साथ जोड़ा।[40] अफगानिस्तान ने मध्यकालीन अवधि में भारत के रणनीतिक चिंतन में भी विद्‌यमान है। अफगानिस्तान की सुरक्षा दिल्ली के सुलतानों के लिए महत्वपूर्ण थी, और बाद में, मुगल काल के दौरान यह काबुल-गजनी-कंधार रक्षा सूत्र के अकबर के वैज्ञानिक फ्रंटियर' के लिए भी उचित स्थान रखता था।[41] भारत पर अफगानिस्तान के मार्ग से आक्रमण किए जाने की सुभेद्‌यता के कारण, ब्रिटिश शासकों ने भारत और जारवादी रूस के बीच एक अंत:वर्ती अंचल के रूप में अफगानिस्तान का विकास किया। भौगोलिक अनवरतता के बावजूद, ब्रिटिश साम्राज्य और जारवादी रूस ने अफगानिस्तान-भारत संयोजनता के बीच एक संपर्क स्थापित किया। तथापि, लोगों-के-लोगों के बीच सांस्कृतिक संपर्क हमेशा सुदृढ़ बने रहे।

बीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत के विभाजन ने भौगोलिक जुड़ाव को समाप्त कर दिया,[42] परंतु राजनीतिक संपर्क निरंतर गहन होता गया। सत्तरवें दशक के अंत में, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप राजनीतिक व्यवस्था और स्थायित्व नहीं ला पाया, बल्कि देश दो विपरीत विचारधाराओं और महाशक्तियों के बीच रण का मैदान बन गया जिससे हिंसा के एक नए चरण का सूत्रपात हुआ जो अभी भी जारी है। सोवियत हस्तक्षेप अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाया, और 1989 में उसकी सेवाओं की वापसी से वहां एक शून्य पैदा हो गया जिसके फलस्वरूप वहां आंतरिक संघर्ष होने लगे और अंतत: तालीबान का उदय हो गया जो 1996 में सत्ता में आया तथा 2001 में अमेरिकी-नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं द्‌वारा हटा दिए जाने तक निरंतर चलता रहा।

अफगानिस्तान में राजनीतिक अव्यवस्था और नागरिक युद्ध ने इस अवधि के दौरान काबुल के साथ दिल्ली में संबंधों में दरार पैदा की। भारत ने तालीबान सरकार को मान्यता नहीं दी तथा उसने काबुल में अपना दूतावास पहले से ही बंद कर दिया था।[43] भारत ने तालीबान को उसकी सुरक्षा, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर प्रांत में एक चुनौती माना था।[44] हालांकि, अफगानिस्तान में तालीबान के बाद की अवधि ने राज्य-निर्माण, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पुनर्निर्माण और विकास के क्षेत्रों में भारत के नवीकृत और व्यापक संबंधों के लिए अवसर उत्पन्न किए। भारत तालीबान के पतन के उपरांत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में शामिल हुआ। यह अफगानिस्तान पर आयोजित लगभग सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी था जिनमें बोन (I-2001 और II-2002), लंदन (I-2006 और II-2010), टोक्यो (2002), पेरिस (2008) तथा अन्य प्रादेशिक सम्मेलन शामिल थे। भारत ने हमेशा इस बात पर बल प्रदान किया है कि अफगान राजनीतिक एकीकरण प्रक्रिया अफगान-नेतृत्व वाली होनी चाहिए।[45]

राजनीतिक संपर्कों के द्विपक्षीय स्तर पर, भारत राज्य-निर्माण की प्रक्रियाओं में अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। इसने संस्थाओं और अवसंरचना की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उदाहरण के लिए काबुल में संसद भवन की इमारत।[46] भारत की भूमिका चुनाव प्रक्रिया को सुकर बनाने में उल्लेखनीय है, इसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, प्रशिक्षित कर्मचारियों का योगदान किया तथा संसद भवन के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराई। भारत और अफगानिस्तान ने मई 2008 में काबुल में स्थानीय शासन के सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।[47] भारत ने एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया तथा अफगानिस्तान में सैन्य टुकड़ियों के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। दूसरी ओर, नई दिल्ली पुनर्गठन और विकास, क्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अफगानिस्तान के पुनर्गठन और विकास के लिए लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर का वचन देने के लिए भारत सबसे बड़े क्षेत्रीय दाता के रूप में उभरकर सामने आया है। पारंपरिक दाताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न रहते हुए, भारत ने अफगान लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मांग-चालित पद्धति का विकल्प चुना है अर्थात् अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण, शिक्षा और महिलाओं की अधिकारिता, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और चुनाव प्रक्रियाएं।

भारत के हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों के अलावा, काबुल के साथ देश के राजनीतिक संबंध विभिन्न कारणों से बाधित हो रहे हैं, जैसे भू-राजनीतिक परिवेश, अप्रभावी क्षेत्रीय सांस्थानिक तंत्र, विदेशी टुकड़ियों की उपस्थिति के प्रति आम अफगानियों का अनादर भाव जिसमें विशेष रूप से सांस्कृतिक मुद्दे और बढ़ती हुई नागरिक मौतें और अफगानिस्तान में विवाद की एक दीर्घकालिक प्रकृति भी शामिल है। नई दिल्ली भी विश्वास करती है कि अफगानिस्तान में इसके प्रत्यक्ष सैन्य संबंधी इसके राजकोष पर भारी दबाव डाल सकते हैं जिनसे अफगान संकट के राजनीतिक समाधन के इसके वर्णित उद्देश्यों को कोई योगदान प्राप्त नहीं होगा तथा यह इसके मुख्य ध्यान को अफगान लोगों की अधिकारिता से कहीं और विपथित कर देगा।

पुनर्निर्माण और विकास अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध के प्रमुख बल प्रदान किए गए क्षेत्र हैं। नई दिल्ली इस बात पर विश्वास करती है कि अफगानिस्तान में एक व्यवहार्य और शांतिपूर्ण राज्य स्थापित करने के लिए एक मुख्य अवयव है। भारत ने अवसंरचना निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उदाहरण के लिए जारांज-डेलाराम सड़क[49] सलमा बांध ऊर्जा परियोजना[50,] पुल-ए-खुमरी संप्रेषण लाइन[51] तथा काबुल, जलालाबाद, कंधार, हेरात और मजार-ए-शरीफ में विद्यालय और अस्पताल। वर्ष 2001 के बाद शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा इन क्षेत्रों में भारत की सहायता को अफगान के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अतयंत महतवपूर्ण माना है।[52] हाल ही में, भारत ने कंधार में एक क्रिकेट स्टेटियम के निर्माण के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर का अनुदान भी प्रदान किया है।[53] कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएसटीयू) के निर्माण में भी सहयोग दिया है।[54] विशेष रूप से कौशल विकास के संदर्भ में, क्षमता निर्माण और महिलाओं की अधिकारिता भी एक

अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें भारत ने अर्थपूर्ण योगदान दिया है। नई दिल्ली अफगान जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, उदाहरण के लिए भारत में शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष अफगानियों को 2000 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिसमें 500 अफगान सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है।[55]

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अफगान जनसंख्या का एक बड़ा भाग 25 वर्ष से कम आयु का है तथा भारत की क्षमता निर्माण और कौशल विकास की नीति युवा संभावनाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह न केवल अफगानिस्तान के विकास के लिए उसकी सहायता करेगा बल्कि युवाओं को आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल करेगा और उन्हें देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए हानिकारक गतिविधियों से भी दूर रखेगा जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध तथा नशीले पदार्थों और मानवों का दुर्व्यापार। अफगान छात्रों के मन में शिक्षा और छात्रवृत्तियों के संबंध के लिए भारत की सहायता को लेकर सकारात्मक भावना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा प्रशिक्षण भारत आकर अध्ययन करने के लिए अफगान छात्रों के प्रमुख आकर्षण के विषय हैं।[56] इसके अलावा, एक अभिनव दृष्टिकोण में 80 से अधिक भारत-समर्थित परंतु अफगान के स्वामित्व वाली विकास परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्था पर हैं।[57] भारत एक सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति है तथा इसे व्यवहार्य लागत पर शासन और विकास के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव है। यह निचले स्तर पर शासन में संवृद्धि करने के लिए अफगानिस्तान को ई-शासन समाधान प्रदान कर सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा जनता को विभिन्न सेवाओं जैसे ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा आदि तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

नई दिल्ली के सॉफ्ट पावर उपायों तथा लोक-केन्द्रित दृष्टिकोण ने अफगानियों के मध्य भारत की एक सकारात्मक छवि सृजित की है। तथापि, उग्रवादियों और आईएसएएफ के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष, कमजोर शासन, व्यापक भ्रष्टाचार तथा अन्य सांस्थानिक और सामाजिक कारकों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता, जिसमें भारत से मिलने वाली सहायता भी शामिल है, ने सीमित परिणाम ही उत्पन्न किए हैं। अफगानिस्तान को अभी युद्धों और नागरिक युद्धों की तबाही से बाहर निकलना है, इसे इसके पुनर्गठन और विकास प्रक्रियाओं के लिए अधिक विकास सहायता की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय दृष्टि से, भारत-पाकिस्तान संबंधों का भी भारत-अफगानिस्तान संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। इस्लामाबाद यह सोचता है कि भारत के अफगानिस्तान के साथ व्यापक विकास संबंध तथा बहुआयामी आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध पाकिस्तान के रणनीतिक हित के लिए हानिकारक होंगे। दूसरी ओर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) की क्षेत्रीय गुटबंदी भी अफगान समस्या के लिए किसी समाधान को प्रारंभ करने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। अफगानिस्तान 2007 के दिल्ली शिखर-सम्मेलन के दौरान दक्षेस में शामिल हुआ था परंतु इस संगठन ने देश की शांति और स्थिरता वापस लाने के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यह भारत के लिए व्यवहार्य नहीं होगा कि वह अफगानिस्तान में अपनी

दीर्घकालिक उपस्थिति की प्रतिबद्धता करें; तथापि, नई दिल्ली देश के पुनर्गठन और विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

सुरक्षा : भारत और अफगानिस्तान के बीच 2011 में रणनीतिक भागीदारी पर हस्ताक्षर किए जाने से दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग की व्याप्ति अत्यंत व्यापक हुई है। तथापि, भारत अभी भी अफगानिस्तान में उग्रवादियों से निपटने के लिए अपनी टुकड़ियां भेजने के प्रति इच्छुक नहीं है। अफगानिस्तान की ओर से अनुरोध किए जाने के बावजूद भारत ने सैन्य संबंधों से अपनी भूमिका को जान-बूझकर सेनाकार्मिकों के प्रशिक्षण तक ही सीमित रखा है। पाकिस्तान के संदेह पर विचार करते हुए नई दिल्ली अफगानिस्तान में अपनी टुकड़ियां तैनात करने के पक्ष में नहीं है। तथापि, अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में स्थित अपनी स्थापनाओं, राजनयिक मिशनों और विकास एवं अवसंरचना परियोजनाओं की संरक्षा करने के लिए इसने अर्धसैनिक बलों का दस्ता तैनात किया है।[58]

यह आशा की जाती है कि भारत अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक भूमिका निभाएगा। ओबामा के प्रशासन ने भी यह संकेत दिया है कि अमेरिका भी उन मामलों में प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, जहां यह कोई 'केन्द्रीय राष्ट्रीय हित' नहीं देखता है।[59] इस परिदृश्य में, अफगानिस्तान और भारत अपने रक्षा सहयोग में विस्तार नहीं करेंगे। काबुल ने भारत से हथियार और उपकरण खरीदने में अपनी रुचि दर्शाई है। भू-राजनीतिक परिवेश पर विचार करते हुए, नई दिल्ली काबुल को प्रत्यक्षत: हथियार प्रदान करने के प्रति सतर्क है क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उग्रवादी भड़क सकते हैं।[60] कथित रूप से, भारत, अफगानिस्तान और रूस अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए एक त्रिपक्षीय भागीदारी विकसित कर रहे हैं। एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके माध्यम से अफगानिस्तान रूस से हथियार खरीदेगा और उसका भुगतान भारत द्वारा किया जाएगा।[61] सुरक्षा के मुद्दे के अलावा, निकट भविष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देश में, भारत के पर्याप्त आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक निवेश की रक्षा किस प्रकार की जाए है। भारत अफगान सरकार के प्राधिकारियों और देश के अन्य राजनीतिक संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के नेशनल फ्रंट की भी अफगानिस्तान में भारत के संबंधों के बारे में सकारात्मक राय है।[62] पूर्व प्रख्यात तालीबान नेता अब्दुल सलाम जईफ ने भारत की यात्रा की थी जिनकी जीवनी ने विश्व को तालीबान के उदय के पीछे छिपे वास्तविक कारणों के विषय में जानकारी दी थी।[63] दूसरी ओर, एक तालीबानी वक्तव्य में कहा गया है, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है" और यह भी कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके "संप्रभुता, समानता, पारस्परिक सम्मान तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के आधार पर भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं।[64] पारंपरिक रूप से, पठानी लोग भारत के निकट रहे हैं तथा तालीबान में भी काफी पठान हैं। अत: उन्हें अफगानिस्तान की मुख्यधारा से अलग करना स्थायी अफगानिस्तान की कल्पना करने वाले किसी भी हितधारक द्वारा अपनाया जाने वाला उचित दृष्टिकोण नहीं होगा।

आर्थिक : भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक भागीदार करार ने भी पुनर्गठन और विकास, आर्थिक संबंध तथा व्यापार और निवेश पर बल प्रदान किया है। खनन एवं हाइड्रोकार्बन को दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख संभावित क्षेत्र माना जाता है।[65] हाल ही में खोजे गए प्राकृतिक संसाधनों ने अफगानिस्तान में भारतीय निवेश के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं। भारतीय कंपनियों को अनुमानित 2 बिलियन टन लौह अयस्क भण्डार के चार ब्लॉकों के खनन के लिए हाजीगक बोली प्रदान की गई है।[66] भारतीय कंपनियों ने अफगानिस्तान के पेट्रोलियम ब्लॉकों तथा तांबा अयस्क खानों के प्रति भी रुचि दशाई है।[67] नई दिल्ली और काबुल अत्यधिक आर्थिक सहयोग के लिए अवसरों की तलाश करने के कार्य में भी व्यस्त हैं। व्यापार के आंकड़े दर्शाते हैं कि अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।[68] तालिका 2 दर्शाती है कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि हुई है जबकि समान अवधि में कजाखस्तान के साथ इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार दोनों देशों के बीच सीधे संयोजन के अभाव के कारण बाधित हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है। थोक व्यापार किसी तीसरे देश से गुजरने वाले किसी मार्ग के माध्यम से ही संभव है। पाकिस्तान की भारत और अफगानिस्तान के साथ साझी सीमाएं हैं, लेकिन, भारत और पाकिस्तान के बीच और साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विद्यमान कटु संबंधों ने नई दिलली और काबुल के मध्य पर्याप्त आर्थिक आदान-प्रदान की संभावनाओं को बाधित किया है। संयोजनता के मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत हालिया वर्षों में गंभीर प्रयास कर रहा है। अगस्त 2012 में गुट-निरपेक्ष संगठन (एनएएम) के शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तेहरान यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी तथा चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए व्यापार और माल प्रेषण को संवर्धित करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया।[69] ईरान के चाबहार पत्तन से अफगानिस्तान से भारत को पहला कंसाइनमेंट, जिसमें अफगानी मेवे थे, सितम्बर, 2013 में मुंबई पहुंचा। चाबहार पत्तन भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए लघुतम मार्ग तथा मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए प्रत्यक्ष पहुंच उपलब्ध कराएगा।[70] अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।[71] कथित रूप से, भारत चाबहार पत्तन का उन्नयन करने के कार्य में तेजी लाने का आशय रखता है। नई दिल्ली ने इस परियोजना के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर प्रदान करने का वचन दिया है।[72] भारत सरकार ने चाबहार परियोजना में निवेश का अनुमोदन कर दिया है।[73] इसके अलावा, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक सेतु भी है। जैसे-जैसे देश की व्यवस्था स्थिर होती जाएगी, भारत के अफगानिस्तान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों में भी वृद्धि होगी तथा काबुल वर्तमान द्विपक्षीय तंत्र को बहुपक्षीय क्षेत्रीय व्यापार और संप्रेषण संधि के रूप में विकसित करते हुए मध्य एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को और विस्तारित करने में एक वाहिका की भूमिका का निर्वहन करेगा।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट व्यापार करार (एपीटीटीए) 2010 पाकिस्तान के भू-भाग के माध्यम से अफगानी माल की आवाजाही की अनुमति देता है। यह करार अफगानी ट्रकों को वाघा सीमा तक अफगान ट्रांजिट निर्यात कार्गो की ढुलाई की अनुमति भी देता है जहां यह कार्गो भारतीय ट्रकों में लाद दिया जाता है। पिछ्ले माहों के दौरान, मेवों और दालों से भरे 2000 से अधिक ट्रकों को वाघा सीमा के माध्यम से भारत लाया गया है।[74] तथापि, पाकिस्तान बाघा सीमा के माध्यम से भारतीय निर्यात को अफगानिस्तान जाने की अनुमति नहीं देता है यह कहता है कि इस पर निकट भविष्य में किसी उपयुक्त समय पर चर्चा की जा सकती है।[75] यदि भारत और पाकिस्तान राजनीतिक संबंधों में सुधार होता है, तो इस्लामाबाद नई दिल्ली को "सर्वाधिक तरजीह प्राप्त राष्ट्र (एमएफएन)" का दर्जा देने पर विचार करेगा, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को पर्याप्त बल प्रदान करेगा। हाल में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ताजिकिस्तान को शामिल करने के लिए उनके ट्रांजिट व्यापार करार की व्याप्ति को व्यापक बनाने के लिए भी सहमति प्रदान की।[76] तीन मध्य एशियाई देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं तथा वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एपीटीटीए, बहुपक्षीय और अंतर्प्रादेशिक व्यापार और ट्रांजिट करार बनाने की संभावना की तलाश करेंगे।

तालिका 2 : भारत के मध्य एशियाई देशों तथा अफगानिस्तान के साथ व्यापार (मिलियन यूएस डॉलर में)

देश	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
अफगानिस्तान	588.74	568.44	643.41	632.18	683.1
कजाखस्तान	291.44	310.59	436.25	426.22	917.84
किर्गिस्तान	27.48	26.98	31.44	37.07	35.18
ताजिकिस्तान	32.57	41.33	30.13	48.01	55.13
तुर्कमेनिस्तान	46.15	35.89	63.41	78.25	87.73
उज्बेकिस्तान	84	81.05	126.43	156.75	145.56

स्रोत : विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

एक बार शामिल किए जाने से, मध्य एशियाई देशों से माल सड़क के द्वारा भारत लाया जा सकता है तथा जब पाकिस्तान भारत को एमएफएन दर्जा प्रदान कर देता है, भारत से भी माल सड़क मार्ग से अफगानिस्तान को और आगे मध्य एशियाई देशों को जा सकता है। इसके अलावा, जब यह पूरी तरह से प्रचालन में आ जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग होगा। चक्रीय सड़क मार्ग के अफगानिस्तान गलियारे की संयोजना का प्रयोग करते हुए व्यापार में एक ओर तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच तथा दूसरी ओर मध्य एशिया और रूस के बीच पर्याप्त वृद्धि होगी।

हालांकि सुरक्षा अफगानिस्तान की किसी भी कार्यवाही पर हावी होती है, देश में व्यवसाय और व्यापार के अवसरों की संभावना द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उभर रही है। भारतीय व्यापारी वाणिज्यिक क्षमता, विशेष रूप से खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में, का उपयोग करने में रुचि ले रहे हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) कुछ सरकारी उद्यम हैं, जो अफगानिस्तान में कार्य कर रहे हैं। भारत अफगान सेवा क्षेत्र का संवर्धन करने की पर्याप्त संभावना को इष्टतम लाभ उठा सकता है। अफगान की अर्थव्यवस्था को संवर्धित करने के लिए, भारत ने 28 जून, 2012 को अफगानिस्तान पर दिल्ली निवेश शिखर-सम्मेलन का आयोजन किया, जो अपने प्रकार का पहला सम्मेलन था जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में व्यापार अवसरों में वृद्धि करना था। भारतीय कंपनियों ने 2001 के बाद से लगभग 25 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।[77] अफगानिस्तान में भारतीय निवेश के लिए सेवा और निर्माण प्राथमिक गंतव्य है। भारत की देश में आर्थिक उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से सहायता आधारित अफगान अर्थव्यवस्था को स्व-संपोषणीय और गुंजायमान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है।

हालांकि भारत को हाजीगक खानों के लिए बोलियां प्रदान की गई हैं तथा इसने तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति अभी हासिल की जानी है। दोनों देशों के बीच संयोजनता अभी भी एक समस्या है तथा खनन किए गए खनिजों को भारत अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कैसे ले जाया जा सकेगा, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान किया जाना है। दूसरी ओर, भारत के आर्थिक संबंध मुख्य रूप से राज्य-चालित हैं, निजी क्षेत्र को सुरक्षा परिदृश्य के सुदृढ़ बनने के उपरांत निवेश और विकास के लिए सामने आने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होगी। नई दिल्ली भारतीय उद्यमियों को कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करते हुए व्यापारियों को व्यापारिक दौरो पर अफगानिस्तान ले जाते हुए, व्यापार का व्यापार के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करके, आदि अफगानिस्तान की व्यापार संभावनाओं के प्रति जागरूक बना रहा है। अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) काबुल चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री तथा भारतीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज परिसंघ (एफआईसीसीआई) के सहयोग के साथ भारत ने काबुल में भारत-अफगानिस्तान अभिनवता भागीदारी मेला आयोजित किया जिसका उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के उद्योगों की अभिनवता को प्रदर्शित करना तथा दोनों देशों के बीच व्यापार को सहयोग प्रदान करना था।[78]

मध्य एशिया में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की संभावना का अन्वेषण करने और उनका उत्कर्षण करने के लिए क्षेत्र के देश अफगानिस्तान में परिस्थिति का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उनके राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय संसाधनों की अभिसारिता कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दो सबसे बड़े क्षेत्रीय निवेशकों अर्थात् भारत और चीन ने अफगानिस्तान पर अपनी प्रथम वार्ता संचालित की। दोनों देशों ने वार्तालाप को निर्माणात्मक और लाभप्रद बताया।[79] इसी प्रकार, भारत ओर पाकिस्तान अफगानिस्तान में साझे अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। अफगानिस्तान में स्थिति

का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय एकीकरण को आगे ले जाते हुए, भारत ईरान ओर अफगानिस्तान ने 2012 में गुट-निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन के दौरान तेहरान में एक बैठक का आयोजन किया।

चित्र 2 : अफगानिस्तान में भारतीय फर्मों द्वारा किया गया क्षेत्रवार निवेश

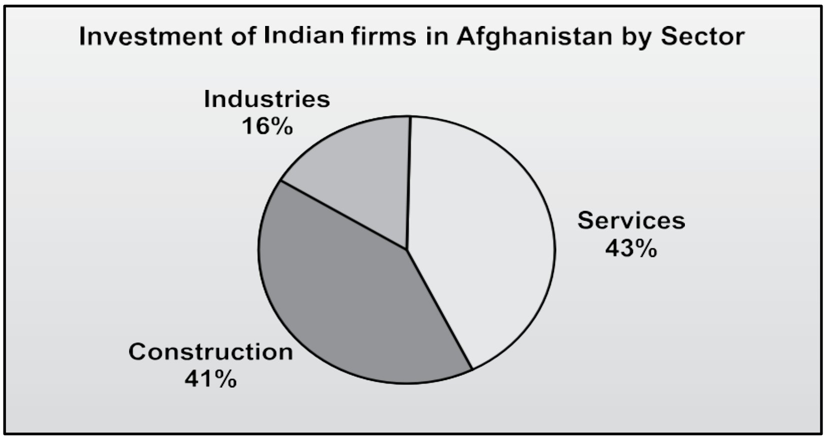

स्रोत : अफगानिस्तान पर दिल्ली निवेश शिखर-सम्मेलन 'भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक संबंध[80]

ऊर्जा: दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और एकीकरण की संवर्धित प्रवृत्ति विद्यमान है। मध्य एशिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों को अफगानिस्तान के माध्मय से पाइपों द्वारा ऊर्जा के अभाव से ग्रस्त दक्षिण एशिया में लाया जा सकता है। हाइड्रोकार्बनों में संपूर्ण क्षेत्र में विकास में संवृद्धि करने तथा आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को व्यापक एवं गतिशील बनाने की संभावना विद्यमान है। 1700 किमी लंबी तथा 9 बिलियन यूएस डॉलर वाली टीएपीआई पाइप लाइन एक महत्वपूर्ण आर्थिक उद्यम है तथा हाल के समय में इस दिशा में कुछ सकारात्मक विकास होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 2012 में करार पर हस्ताक्षर किया जाना तथा परियोजना के लिए संव्यवहार सलाहकार के रूप में एशिया विकास बैंक (एडीपी) का हाल में किया गया चयन शामिल है।[81] एक विशेष प्रयोजन व्हीकल सृजित करने का निर्णय लिया गया है जिसे न्यूजर्सी, यूएसए में पंजीकृत किया जाएगा तथा तापी लिमिटेड द्वारा उस पर कार्य किया जाएगा।[82] हितधारक पाइपलाइन का निर्माण करने के लिए कंसोर्टियम नेतृत्वकर्ता और अनुभवी फर्म की तलाश कर रहे हैं।[83] फ्रांसीसी ऊर्जा बहुराष्ट्रीय कंपनी 'टोटल' कथित रूप से एडीपी के सहयोग से कंसोर्टियम का नेतृत्व करने के लिए रुचि ले रही है।[84] अनेक राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों तथा बढ़ती हुई लागतों के बावजूद, समस्त हितधारक इसकी व्यवहार्यता के बारे में सुनिश्चित हैं तथा इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक हैं।

ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दिए जाने तथा परमाणु मुद्दे पर बड़ी ताकतों के साथ किए जाने वाले संभावित करार ने तेहरान को अपनी प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ईरान के पास विश्व में दूसरा विशालतम प्राकृतिक गैस भण्डार है[85] तथा उसने दक्षिण एशियाई बाजार तक पहुंच बनाने के लिए टीएपीआई उद्यम में शामिल होने इच्छा जताई है।[86] भारत और पाकिस्तान के अलावा, ऊर्जा के अभाव वाले एक अन्य दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश ने कुछ वर्ष पूर्व टीएपीई परियोजना में शामिल होने की अपनी रुचि को पहले ही दर्शा

दिया है।[87] परियोजना में शामिल होने के अपने प्रयासों को नवीकृत करते हुए बांग्लादेश ने हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के साथ बातचीत की है तथा अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने की योजना भी बनाई गई है।[88] अधिक भागीदारी न केवल आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि करेगी बल्कि परियोजना के संभावित जोखिमों को भी न्यूनतम बताया जा सकेगा। इसके अलावा, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व भारत के पंजाब से पश्चिम बंगाल तक बिछाई गई पाइपलाइन उत्तरी मैदान में विद्यमान पाइपलाइन के साथ उद्योग के लिए एक वरदान सिद्ध होगी।

तापी में हासिल की गई प्रगति ने उत्तर-दक्षिण अक्ष के साथ-साथ रूस से भारत तक की एक अन्य महत्वाकांक्षी ऊर्जा पाइपलाइन पर चर्चा प्रारंभ कर दी है। दोनों ही देश रूस से भारत तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि रूस अपने ऊर्जा निर्यातों को यूरोपीय बाजारों से एशियाई बाजारों तक विस्तारित करने का इच्छुक है तथा भारत तेल की मांग में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, इस ऊर्जा भागीदारी में यूरेशियाई क्षेत्र में ऊर्जा बाजार के समीकरण को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता है।

आगे चलकर, बिलियन से अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध होती जनसंख्या रूस के लिए एक आकर्षक बाजार होगा और इसके परिणामस्वरूप भारत भी रूसी कच्चे तेल की पहुंच प्रदान करने के अतिरिक्त पेट्रो-रसायन उत्पादों को परिष्कृत और निर्यात कर सकेगा। यूक्रेन के संकट तथा पश्चिम के आर्थिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए रूस चीन और भारत के साथ ऊर्जा भागीदारी का विस्तार करने में रुचि ले रहा है। रूस और चीन ने 21 मई, 2014 को 400 बिलियन यूएस डॉलर के गैस सौदे पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। नई दिल्ली और मास्को ने 'योजनाबद्ध टीएपीआई के मार्ग के साथ-साथ एक अन्य पाइपलाइन के निर्माण की संभावना पर जुलाई, 2014 में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन के दौरान चर्चा की है। भारत में रूसी राजदूत एलेक्जेंडर कडाकिन ने कहा, "हम (भारत और रूस) स्थल के माध्यम से एक पाइपलाइन का निर्माण करने की भारतीय पहल की व्यवहार्यता की जांच करने की योजना बना रहे हैं जो या तो पूर्व में निर्धारित टीएपीआई मार्ग के साथ-साथ अथवा हिमालय के माध्यम से ले जाई जाएगी।"[90] भारत ने कजाखस्तान से भी एक अन्य तेल पाइपलाइन प्रस्तावित की है। 100 किमी लंबी भारत-कजाखस्तान पाइपलाइन कजाखस्तान में शिमकेंट से प्रारंभ होगी टीएपीआई मार्ग का अनुसरण करने के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह उजबेकिस्तान के माध्यम से गुजरेगी।[91]

मध्य एशिया न केवल हाइड्रोकार्बन संसाधनों से परिपूर्ण है, इसमें जल-विद्युत के लिए भी व्यापक संभावनाएं हैं। किर्गिज गणराज्य और ताजिकिस्तान क्षेत्र की कुल ऊर्जा आवश्यकता की पर्याप्त रूप से पूर्ति कर सकते हैं तथा न्यूनतम निवेश के साथ अतिरिक्त मात्रा का निर्यात कर सकते हैं। इस संभावना का लाभ उठाने के लिए, अमेरिका द्वारा समर्थित सीएएसए परियोजना की दक्षिण एशियाई-मध्य एशियाई ऊर्जा सहयोग के लिए परिकल्पना की गई है। सीएएसए-1000 ऊर्जा संप्रेषण रेखा[92] उत्पादक देशों किर्गिस्तान और ताजिकस्तान तथा उपभोगकर्ता देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की परियोजना है। यह परियोजना पहले ही आरंभ की जा चुकी है तथा इसे विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा समर्थित किया गया है। अमेरिका द्वारा 2013 में

दी जाने वाली 15 मिलियन यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता ने परियोजना की व्यवहार्यता में वृद्धि कर दी है तथा इससे क्षेत्र में अत्यधिक राजनीतिक और आर्थिक अभिसारिता को प्रोत्साहन मिला है।[93] पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ट्रांजिट शुल्क पर सहमति व्यक्त कर दी है तथा उनके बीच क्षेत्रीय विद्युत व्यापार पर करार पर सीएएसए-1000 विद्युत संप्रेषण एवं व्यापार परियोजना के भाग के रूप में हस्ताक्षर किए गए।[94] हाल में, भारत को भी परियोजना में शामिल करने की मांग की गई है ताकि वह भी इस किफायती और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा सृजन परियोजना के लाभान्वित हो सके। ग्रीष्मकाल के दौरान बिजली की कमी तथा इस दौरान उत्पादक देशों में इसकी अतिरिक्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत न्यूनतम अवसंरचना स्थापित करके और विद्यमान विद्युत ग्रिडों का प्रयोग करते हुए इस परियोजना से लाभान्वित हो सकता है।[95] ऐसी परियोजनाएं यह दर्शाती हैं कि बहुपक्षीय संबंधी मध्य एशिया और दक्षिण एशिया, दोनों ही के लिए लाभप्रद होंगे।

अफगानिस्तान में बहुपक्षीय प्रक्रियाओं में भारत की सहभागिता

जैसा कि स्पष्ट है, भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व बहाल करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपना रहा है। नई दिल्ली भी महत्वपूर्ण अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन (आईसीसीए) पहल को सहयोग प्रदान कर रहा है। यह कार्यक्रम अफगानिस्तान को मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की व्यापक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करते हुए वहां स्थायित्व लाने की परिकल्पना करता है। भारत, जिसने 2006 में नई दिल्ली में द्वितीय आईसीसीए सम्मेलन की मेजबानी की थी, आर्थिक क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता करता है, जो मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास और अंतर्वेशी विकास पर केन्द्रित होते हैं। भारत के कार्यक्रम अफगान समाज में निचले स्तर पर विद्यमान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का निराकरण करने पर केन्द्रित होते हैं। भारत इस्तांबूल प्रक्रिया में अपनाए गए व्यापार, वाणिज्य और निवेश अवसरों सीबीएम (टीसीआई-सीबीएम) का नेतृत्व भी करता है।[96]

नई दिल्ली अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक संगठनों में प्रतिभागिता करती है जो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में रणनीतिक परिवेश को आकार देने के लिए प्रासंगिकता रखते हैं। भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का प्रेक्षण सदस्य भी है तथा उसने इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया है। एससीओ क्षेत्रीय राजनीतिक सुरक्षा और नृजातीय समस्याओं पर चर्चा करने तथा उनका समाधान ढूंढने के लिए क्षेत्रीय देशों के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। भारत वर्ष 2001 से ही अफगानिस्तान संकट के लिए राजनीतिक समाधान तलाशने तथा पुनर्गठन और विकास के लिए वित्तीय संसाधन सृजित करने के लिए वैश्विक राय का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के सम्मेलन में भागीदारी भी कर रहा है। विशिष्ट पहलकदम उठाते हुए, नई दिल्ली में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने तथा अफगानिस्तान में आर्थिक संबंधों को गहन बनाने के लिए चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ताएं आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय शिखर-सम्मेलनों का आयोजन किया।

अफगानिस्तान : उभरती क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता का केन्द्र

अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक, विशेष रूप से ऊर्जा संबंधी अभिविन्यास में अवस्थित है, यह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया तथा पूर्व एशिया के क्षेत्रों को चीन के माध्यम से परस्पर जोड़ता है। अफगानिस्तान की स्थिति क्षेत्रीय देशों को प्रभावित करती है तथा वे इसके फलस्वरूप अफगानिस्तान में स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। काबुल अपनी वर्तमान स्थलरुद्ध भौगोलिक अवस्थिति की त्रुटि को भौगोलिक लाभ में प्रभावशाली रूप से संपरिवर्तित कर सकता है तथा यह क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों का महत्वपूर्ण मंच बन सकता है।

दक्षिण एशिया : दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रादेशिक गतिशीलता संश्लिष्ट बनी हुई हैं तथा वे मुख्य रूप से उच्च राजनीति द्वारा शासित होती हैं। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय राजनीतिक परिवेश ने अफगानिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा समस्याओं के लिए स्थायी समाधान तलाशने की प्रक्रिया को बाधित किया है। दो प्रमुख दक्षिण एशियाई शक्तियां भारत और पाकिस्तान, ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण अपनए हैं, जिनके फलस्वरूप वे अफगानिस्तान की सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों के बारे में किसी भी नीतिगत सामंजस्य तक पहुंच पाने में असफल रहते हैं। भारत के अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों को पाकिस्तान में इस चिंता के साथ देखा जा सकता है कि वे पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर नई दिल्ली को एक रणनीतिक लाभ प्रदान करेंगे। इस्लामाबाद विशेष रूप से दक्षिण अफगानिस्तान में भारतीय कांसुलेटों से अत्यंत परेशान था जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित थे। उसने भारत पर पृथग्वादी ब्लू आंदोलनों को सहायता देने का आरोप लगाया है।[97] दूसरी ओर, सुरक्षा के अतिरिक्त, भारत काबु को अपना पारंपरिक मित्र मानता है तथा अफगानिस्तान को मध्य एशिया से वातायन के रूप में देखता है। हाल के वर्षों में सुरक्षा ही दोनों देशों के बीच अभिसारिता का प्रमुख कारण रही है तथा काबुल भारत को अपना एक रणनीतिक भागीदार तथा पड़ोस में एक बड़ी अर्थव्यवस्था मानता है जो देश के रूपांतरण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली यह मानता है कि काबुल के साथ उसका संबंध पाकिस्तान के विरुद्ध निर्देशित नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रकृति ने अफगानिस्तान की समस्याओं का समाधान करने में दक्षेस के प्रादेशिक संगठन को प्रभावशाली रूप से निरर्थक बनाया है। अफगानिस्तान के दक्षेस के सदस्य के रूप में वह अफगानिस्तान में संकट का समाधान करने के लिए एक मजबूत और स्थायी क्षेत्रीय मंच बन सकता है। तथापि, भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता ने विशेष रूप से अफगानिस्तान में इस संगठन को कमजोर बनाया है।

इस्लामाबाद में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एक सरकार से सत्ता दूसरी सरकार को सफलतापूर्वक रूप से सौंपे जाने के प्रथम स्थानांतरण के साथ ही सरकार में आए परिवर्तन, अस्त-व्यस्त सुरक्षा स्थिति, 2014 में अफगानिस्तान से आईएसएएफ की निकासी तथा काबुल और इस्लामाबाद के बीच राजनीतिक समझ में आया सुधार क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य एक अर्थपूर्ण सहयोग के लिए आशा उत्पन्न करने के प्रमुख कारण हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में नई सरकार ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए अति-सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यभार संभालने के अवसर पर दक्षेस देशों के प्रमुखों को आमंत्रित करते हुए

क्षेत्रीय देशों को एकजुट करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की है। दक्षेस देशों को भेजे गए निमंत्रण ने यह सुदृढ़ संदेश प्रेषित किया कि नई दिल्ली सभी पड़ोसियों के साथ निर्माणात्मक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाने की इच्छा रखती है। भारत और पाकिस्तान वार्ताओं और वृहद् आर्थिक संबंधी पुनर्जीवित करने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। नवम्बर, 2014 में काठमांडू में आयोजित किए जाने वाले दक्षेस शिखर-सम्मेलन से पूर्व अपने संबंधों को और सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों द्वारा अधिक गंभीर प्रयास किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वे "पाकिस्तान के आर्थिक हित" को भी ध्यान में रखेंगे।[98] हालांकि, दक्षेस को ऊर्जावान बनाने के लिए उच्च स्तरीय राजनीति सहक्रियाएं और भरोसे की भावना अनिवार्य हैं, भारत और पाकिस्तान को क्षेत्र में पर्याप्त व्यापार और संयोजनता पर ध्यान-केन्द्रित करना चाहिए जो आर्थिक अंत:आश्रिता में वृद्धि कर सकता है तथा विवाद के जोखिम को कम कर सकता है।

भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय एलएनजी पाइपलाइन पर भी बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐसी पाइपलाइन दो मुख्य कारणों से व्यवहार्य है : पहला, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत बिजली के गंभीर संकट का सामना कर रहा है तथा देश के पास कथित रूप से कोई एलएनजी आयात अवसंरचना नहीं है। दूसरे, भारत के पास दाहेज, गुजरात से इसके पंजाब प्रांत के लिए एक एलएनजी पाइललाइन है। दोनों देशों के बीच 10 किमी लंबी पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है ताकि पाकिस्तान एलएनजी संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन में समर्थ हो सके। यह पाइपलाइन भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भी पाकिस्तान के रास्ते से टीएपीआई पाइपलाइन के माध्यम से मध्य एशिया से प्राकृतिक गैस लाने का प्रयास कर रहा है।[99] भारत में नई सरकार ने पाकिस्तान को हाइड्रोकार्बन निर्यात करने के अपने आशयों को सकारात्मक रूप से दर्शाया है। एक अन्य सकारात्मक घटनाक्रम में, भारत और पाकिस्तान गैस मूल्य-निर्धारण सूत्र पर सहमत हुए हैं। दोनों देश भारत से पाकिस्तान को बिजली की आपूर्ति की संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत एक ग्रिड कॉरीडोर के माध्यम से पाकिस्तान को बिजली की आपूर्ति कर सकता है जो 500-1000 मेगावाट विद्युत रख सकता है।[100].ऐसी बहु-हितधारक परियोजनाएं वृहद् क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए आगे राजनीतिक और आर्थिक परिवेश सृजित करेंगी।

यह भी विश्वास किया जाता है की यूएस-ईरान परमाणु सौदा ईरान-पकिस्तान-भारत पाइपलाइन को पुनःप्रारंभ करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करेगा।[101] दूसरी ओर, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों में व्याप्त मतभेदों का समाधान करने तथा अफगानिस्तान में तालीबान के साथ समाधान प्रक्रिया के लिए अनुकूल परिवेश का सृजन करने के लिए पहलकदम उठा रहा है। वर्ष 2013 में पूर्व अफगानिस्तान राष्ट्रपति हामिद कर्जई की इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए सहयोग को विस्तारित किया। इसने समझौता प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए कुछ प्रमुख तालीबान हस्तियों जैसे हाकिम बारादर को रिहा किया ।[102] प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी लोया जिर्गा की पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान का जवाबी दौरा किया तथा कतिपय मुद्दों पर दोनों देशों के बीव मतभेदों का समाधान करने और दोनों देशों को लाभ

पहुंचाने वाले व्यापक आर्थिक सहयोग को सुकर बनाने के लिए ईरान और 5+1 के बीच आंतरिक परमाणु सौदे पर हस्ताक्षर किए।[103] पाकिस्तान भारत के साथ यह दृष्टिकोण साझा करता है कि समझौता प्रक्रिया अफगानी-नेतृत्व वाली तथा अफगान-स्वामित्व वाली होनी चाहिए।

अमेरिका भी अफगानिस्तान में भारत के अधिक गहन संबंधों के लिए वृहद् भारत-पाक सहयोग का समर्थन करता है। वाशिंगटन अफगानिस्तान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सहक्रियाओं का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका यह मानता है कि अफगानिस्तान में स्थायित्व की मांग सभी क्षेत्रीय देशों के लिए साझी है जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है तथा यह विश्वास करता है कि अफगानिस्तान में स्थायित्व और सुरक्षा दोनों देशों के बीच 'निर्माणात्मक संबंधों का विषय' है।[104]

मध्य एशिया : अफगानिस्तान की भू-राजनीतिक अवस्थिति, इसकी जनसंख्या की बहु-नृजातीय संरचना तथा इसकी विविध धार्मिक आस्था प्रणालियां इसकी सीमाओं के इसके संबंध को प्रतिपादित करती है। 2014 में अफगानिस्तान से सेनाओं के वापस ले लिए जाने तथा दोनों देशों के बीच एक छिद्रित सीमा के साथ ताजिकिस्तान राजनीतिक और सुरक्षा अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित है। ताजिकिस्तान को यह भय है कि निष्कासित तालीबान ताजिकिस्तान में उग्रवादियों को समर्थन प्रदान करेगा और देश को अस्थिर बनाने का प्रयास करेगा। किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए, दुशानबे ने व्यापक उपाय किए हैं जिसमें मास्को के साथ इसके सैन्य आधार को विस्तारित करने का सौदा भी शामिल है, जिसे संसद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया गया है,[104] जिसके तहत अमेरिका से उन्नत उपकरण खरीदे गए हैं और आतंकवाद-विरोधी एवं नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रशिक्षण भी शामिल है[105] तथा गोर्नो-बाडाखशान क्षेत्र पर इसके नियंत्रण को कड़ा बनाने का प्रयास किया है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिसके अंतर्गत 2012 में एक प्रमुख सैन्य अभियान संचालित किया गया है और अपने दक्षिणी पड़ोसियों के साथ इसकी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए रूस के साथ सहयोग में वृद्धि की है। इसने किसी भी भावी परिदृश्य का सामना करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया है।

दूसरी ओर उज्बेक प्राधिकारियों को इस बात की चिंता है कि एक सुदृढ़ तालीबान उज्बेक उग्रवादियों को उज्बेकिस्तान में उनके गैर-सरकारी प्रचालनों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसा माना जाता है कि अनेक उज्बेक तालीबान आंदोलन में शामिल हो गए हैं तथा वे उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ताशकंद अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति तथा देश में उज्बेकिस्तान के इस्लामी आंदोलन के क्रियाकलापों में भी पारस्परिक संबंध देखता है। उभरते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, उज्बेक सरकार ने दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। उसने काबुल के साथ अपने सहयोग में वृद्धि की है और साथ ही अपनी सुरक्षा उपायों को भी सुदृढ़ बनाया है। हाल ही में, उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक रेलवे लाइन पूर्ण की है, जो उत्तरी अफगानिस्तान में पहली रेलवे लाइन है।[106] ताशकंद काबुल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलावा अफगानिस्तान में सामाजिक अवसंरचना का विकास कर रहा है। उज्बेक सरकार अफगानिस्तान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पश्चिमी देशों के साथ सहयोग कर

रहा है तथा इसने अपने भू-भाग के माध्यम से उत्तरी वितरण नेटवर्क मार्गों की अनुमति दी है। तथापि, उज्बेक प्राधिकारी संभवत: यह विचार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान 2014 में रूपांतरण के लिए तैयार नहीं है तथा वे देश की अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और स्वयं ही संभावित अनबनों से निपटने को अधिक तरजीह प्रदान कर रहे हैं।[107] ताशंकद ने हाल ही में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) छोड़ दिया है तथा ऐसी नीति अपनाई है जो देश में किसी भी विदेशी सेना की अनुपस्थिति को प्रतिबंधित करती है।

मध्य एशिया में अफगानिस्तान का एक अन्य पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के भावी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। तुर्कमेन सरकार अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह मानवीय सहायता तथा लोगों के लिए निर्माण सुविधाएं प्रदान करने के अलावा 'अनुकूल शर्तों' पर देश को बिजली की आपूर्ति भी करती है।[108] हाल में हस्ताक्षरित टीएपीआई गैस पाइपलाइन करार अफगानिस्तान को एक क्षेत्रीय विद्युत केन्द्र में रूपांतरित कर सकता है तथा साथ ही अपने भू-भाग के माध्यम से पाकिस्तान और भारत को तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त गैस की आपूर्ति के लिए प्रेषण शुल्क के रूप में राजस्व की आपूर्ति भी करा सकती है।

तीन मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उब्जेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीधी सीमाएं लगती हैं, अत: वे उनके पड़ोस मं स्थिति को सामान्य बनाने वाले उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। दो अन्य मध्य एशियाई देश जिनकी अफगानिस्तान के साथ सीधी सीमाएं नहीं लगती हैं अर्थात् कजाखस्तान और किर्गिस्तान 2014 की कमजोरियों का सामना करने तथा देश को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा के स्थान पर आर्थिक पहलुओं पर अधिक ध्यान-केन्द्रित कर रहे हैं।

कजाखस्तान अफगानिस्तान में समस्याओं का समाधान करने में अत्यंत सक्रिय है। राजनीतिक दृष्टि से, अस्ताना मध्य एशिया में क्षेत्रीय वार्ताओं में संलग्न है। क्षेत्र की विशालतम और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होने के नाते, यह अफगानिस्तान को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह अफगान छात्रों को 1000 विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियां प्रदान करने के अलावा देश को हजारों टन खाद्य-सामग्री, ईंधन और उपकरणों का वितरण कर रहा है। कजाखस्तान की प्रमुख पहलें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश तथा साथ ही कृषि, शिक्षा और अवसंरचना में वृद्धि करने पर केन्द्रित हैं।[109]

निष्कर्ष

अफगानिस्तान की समस्या का हल करने के लिए विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य अत्यंत अनुकूल प्रतीत होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें अमेरिका, बहुपक्षीय संगठन, पड़ोसी और क्षेत्रीय देश शामिल हैं, इसके विषय में चिंता करता है तथा सतत् वैश्विक आर्थिक मंदी में अफगानिस्तान को स्थिर नाए रखने के लिए सतत् प्रयास करता है। दूसरी ओर,

आम अफगान लोगों तथा सशस्त्र विपक्षी संगठनों की ओर से यह सुदृढ़ भावना उठती है कि सभी देशों में देश को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक संकट को समाप्त किया जाना चाहिए।

कोई भी अन्य देश, सिवाए उनके जो अफगानिस्तान की भू-राजनीतिक स्थिति से समीपता रखते हैं, देश की अस्थिरता के कारण अधिक प्रभावित नहीं हैं। इसके फलस्वरूप, अफगानिस्तान की स्थिति दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में इसके पड़ोसी देशों को अधिक प्रभावित करती है। हालांकि, अफगानिस्तान की स्थिति राजनीति परिवेश से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर उपलब्ध करती है, यह क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा अधिक राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों के लिए आदर्श अवसर उपलब्ध कराती है। दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के क्षेत्र अंतर और अंतरा-क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के संदर्भ में पूर्णत: गैर-अन्वेषित रहे हैं। अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व में व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने की तथा यह दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एकीकरण करने की क्षमता है। व्यापक क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक संबंध न केवल विकास और समृद्धि लेकर आएंगे बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक और रणनीतिक वैमनस्यता के जोखिमों को भी कम करेंगे।

अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति अंतर्वेशी, सतत् और प्रतिभागी रही है। नई दिल्ली अफगानिस्तान में राजनीतिक और विकास प्रक्रियाओं में निरंतर शामिल रही है। यह अर्थपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है जिन्हें अफगान स्थापना तथा आम अफगानियों दोनों ही के द्वारा सकारात्मक रूप से लिया गया है। इतिहास और भू-राजनीति को ध्यान में रखते हुए, अफगानिस्तान में सैन्य टुकड़ियों को भेजना उचित नहीं है। जैसा कि अफगान सरकार द्वारा मांग की गई है, उसे अत्यधिक हथियारों की आपूर्ति करना देश के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, तथापि, भारत के परिप्रेक्ष्य से, आपूर्ति किए गए हथियारों का नियंत्रण और निगरानी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दृष्टि से एक जटिल विषय बन सकता है। सुरक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मध्य एशिया तक पहुंच अफगानिस्तान में भारत के रणनीतिक हित हैं, जिन्हें अफगानिस्तान के राष्ट्रीय बलों को भारी हथियारों से लैस किए बिना भी हासिल किया जा सकता है।

सतर्क दृष्टिकोण के बावजूद, 2014 के उपरांत अफगानिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति को प्रोत्साहित करने के फलस्वरूप देश के साथ भारत के विकास की भागीदारी को जारी रखने और उसमें संवृद्धि करने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में, भारत अफगानिस्तान की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहा है तथा क्षेत्रीय देशो जैसे पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ मेल-जोल बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान मध्य एशिया का वातायन बनने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता और भू-रणनीतिक स्थिति का प्रयोग कर रहा है। एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में, भारत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहायोग के मॉडल के रूप में उभरने के लिए अफगानिस्तान की सहायता करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

पाद-टिप्पणियां

1. त्रोफिमोव, यारोस्लाव, "तालीबान्स स्प्रेड इन्टू नार्थईस्ट स्पार्क्स फियर्स", दि *वॉल स्ट्रीट जर्नल*, 6 सितंबर, 2013. http://online.wsj.com/ news/articles/SB10001424127887324463604579042863355114436 (3 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
2. डॉयचे वेले, "अंडरस्टैंडिंग अफ़गानिस्तान्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ", 30 सितंबर, 2014. http://www.dw.de/understanding- afagonistans-Chief-Executive-Officer / a-17965187 (3 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
3. द हिंदू, "तालिबान 'फ्यूरिअस' ओवर फ्लैग इश्यू", 22 जून, 2013. http: // www.thehindu.com/news/international/south-asia/taliban-furious- over-flag-issue / article4840278। ece (15 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
4. बीबीसी, "एमनेस्टी अर्जेस ईरान टू स्पेयर हैंगिंग सर्वाइवर्स लाइफ", 17 अक्टूबर, 2013। http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east- 2456 3453 (15 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
5. एमनेस्टी इंटरनेशनल, "एडिक्टेड टू डेथ: एक्ज़ीक्यूटिव फ़ॉर द ड्रग ऑफेंस फ़ॉर ईरान", लंदन, 2011, पृष्ठ.16. http://www.amnesty.org/ en/library/asset/MDE13/090/2011/en/0564f064-e965-4fad-b062- 6de232a08162/ mde130902011en.pdf (15 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
6. वान डायक, जेरे, "एज़ अमेरिका फाइट्स, चाइना गेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स", सीबीएस, 19 जुलाई, 2013। http://www.cbsnews.com/news/as-america-fights-china- get-contract / (Accessed 3 नवंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।
7. अल जज़ीरा, "अशरफ़ गनी स्वोर्न इन एज अफ़ग़ान प्रेसिडेंट", 29 सितंबर, 2014। http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/afghaistan-toaugurate-new-President-ghani-201492915136473986.html (14 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
8. खान, ताहिर, "अफगान सुलह: अमेरिका-तालिबान इंपेस के सामने लड़ाई में सउदी वसंत", द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, 24 अगस्त 2012. http://tribune.com.pk/story/4n491/afagan-reconciliation- http://tribune.com. pk/story/425491/afghan-reconciliation-saudis- spring-into-action-in-face-of-us-talib an-impasse// (6 अक्टूबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
9. अमीरी, शरीफ, "प्रेसिडेंट घानीज़ फर्स्ट वीक इन ऑफिस", टोलो न्यूज, 6 अक्टूबर, 2014. http://www.tolonews.com/en/afaganistan/16640- president-ghanis-first-week-in-office (14 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
10. लोधी, मालेहा, "अफगानिस्तान: द चैलेंज अहेड", द न्यूज़, 14 अक्टूबर, 2014. http://www.thenews.com.pk/Todays-News-9-278 209-Afghanistan-the-challenge-ahead (15 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

11. शालिज़ी, हामिद, “तालिबान रिजेक्ट अफगान यूनिटी गवर्नमेंट पैक्ट एज यू.एस. 'शैम', रायटर्स, 22 सितंबर, 2014. http://in.reuters.com/ लेख / 2014/09/22/afagonistan-politics-idINL3N0RN2VI20140922 (15 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
12. इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, "ए फ़ोर्स इन फ्रैगमेंट्स: रिकंस्टुटाइजिंग द अफगान नेशनल आर्मी", 12 मई, 2010. http: //www.crisisgroup। org / en / regions/asia/south-asia/afghanistan/190-a-force-in-fragments- reconstituting-the-afgha n-national-army.aspx. (14 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
13. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान, “अफगानिस्तान में राजनीतिक दल; 2009 और 2010 के चुनावों के बाद राजनीतिक दलों की स्थिति की समीक्षा”, जून, 2011, पृष्ठ 16, 29, 30, 48. http://www.ndi.org/files/ Afghanistan-political-parties-july-2011.pdf. (13 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
14. वाल्श, डेक्लान और अहमद, आज़म, "मेलिंग अलायंस, यू.एस. एंड अफगानिस्तान साइन लॉन्ग-टर्म सिक्योरिटी एग्रीमेंट", द न्यू यॉर्क टाइम्स, 30 सितंबर 2014. http://www.nytimes.com/2014/10/01/ world/asia/afghanistan-and-us-sign-bilateral-security-agreement. html?_r=0 (15 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
15. तदेव

16. द हिन्दू, "फोकस मे शिफ्ट टू ट्रेनिंग अफगान ट्रेनर्स", 7 अगस्त 2014. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/focus- may-shift-to-training-afghan-trainers/article6289336.ece (3 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
17. स्वामी, प्रवीण, "तालिबान फ्लश विथ कैश, वार्न्स यूएन रिपोर्ट", द हिंदू, 16 जून, 2014. http://www.thehindu.com/news/national/ taliban-flush-with-cash-un-warns /article6116798.ece (3 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
18. नोर्डलैंड, रॉड, "प्रोडक्शन ऑफ़ ओपियम बाई अफ़गान इज अप अगेन", द न्यू यॉर्क टाइम्स, 15 अप्रैल, 2013. http://www.nytimes.com/2013/04/16/ world/asia/afghanistan-opium-production-increases-for-3rd-year. html (21 सितंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
19. नशीले पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, अफ़ग़ानिस्तान अफीम जोखिम मूल्यांकन 2013, अप्रैल, 2013। https://www.unodc.org/documents/ islamicrepublicofiran // ORAS_report_2013_p312.pdf (15 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
20. अकमलजोन, अब्दुल्लायेव, “मध्य एशिया में अवैध ड्रग तस्करी की संवीक्षाकरण संभावनाएं. ओ. टेनरिसेवे (संपा.) की 9/11 के बाद से अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया: क्षेत्रीय सुरक्षा में नाटो की भूमिका में, IOS प्रेस BV, एम्स्टर्डम, 2013, पृ. 62.
21. विश्व बैंक, "अफगानिस्तान ओवरव्यू", 2013. http: // www। worldbank.org/en/country/afaganistan/overview (13 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
22. विश्व बैंक, जीडीपी विकास (% वार्षिक) http://data.worldbank. org/indicator/N Y.GDP.MKT P.KD.ZG?order=wbapi_data_

value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value- first&sort=desc (23 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

23. दि न्यू यॉर्क टाइम्स, "अफगानिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस", 20 जुलाई, 2012. http://www.nytimes.com/2012/07/21/opinion/afghanistans-eco nomic-challenges.html (30 अगस्त 2013 को एक्सेस किया गया)।

24. दि गार्जियन, "यूएन एजेंसी कट्स अफगानिस्तान फ़ूड राशन अस डोनेशन्स ड्राय अप", 14 अक्टूबर 2014। http://www.theguardian.com/ world/2014/oct/14/world-food-programme-cuts-rations-afghanistan (16 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

25. वर्ल्ड बैंक, "दि वर्ल्ड बैंक डेटा: टैक्स रेवेन्यू (जीडीपी का%)", 2011). http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS (24 सितम्बर 2014 को एक्सेस किया गया)।

26. विश्व बैंक, "अफगानिस्तान इन ट्रांजीशन : लुकिंग बियॉन्ड 2014, खंड 2: मुख्य रिपोर्ट", मई, 2012. http://siteresources.worldbank. org /AFGHANISTANEXTN/Images/305983-133495462 9964/AF Transition2014Vol2.pdf (दिसंबर 13, 2013 को एक्सेस किया गया)।

27. यूएनईपी, " यूएनईपी इन अफगानिस्तान: लेइंग दि फाउंडेशन्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट", 2011, पी। 5. http://www.unep.org/pdf/ UNEPinAfaganistan.pdf (30 अगस्त 2013 को एक्सेस किया गया)।

28. हैदरी, एम.ए, "अफगानिस्तान: सिल्क रोड टू ऑपर्चुनिटीज", डिप्लोमैटिक ट्रैफिक, (वर्ष का उल्लेख नहीं). http: //www.diplomatictraffic.com/ opinions_archives.asp? ID=156 (16 दिसंबर, 2012 को एक्सेस किया गया)।

29. रिसेन, जेम्स, "यू.एस. आइडेंटिफाईज़ वास्ट मिनरल रिचेस इन अफगानिस्तान", द न्यूयॉर्क टाइम्स, 13 जून, 2010 http://www.nytimes.com/2010/06/14/ world/asia/14minerals.html?pagewanted=all,, (23 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।

30. घनिजादा, "माइनिंग फॉर मिनरल्स वर्थ $ 3 ट्रिलियन इन अफगानिस्तान", खामा प्रेस, 10 मार्च, 2014, http://www.khaama.com/mining-for- minerals-in-afghanistan-4028 (23 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया))।

31. बीबीसी, "अफगान मिनरल्स मीन 'सेल्फ सफिसीएन्सी' इन 10 इयर्स", 25 जून, 2010. http://www.bbc.co.uk/news/10412085 (10 दिसंबर 2012 को एक्सेस किया गया)।

32. तदेव।

33. यूएनडीपी, "अफगानिस्तान, राष्ट्रीय संयुक्त युवा कार्यक्रम (एनजेवाईपी)"। http://www.undp.org.af/whoweare/undpinafghanistan/Projects/ dcse/prj_youth.htm (Accessed July 23, 2013); UNDP, Afghanistan. http://www.undp.org.af/who weare/ undpnafghanistan/Projects/dcse/ prjyouth.htm (10 दिसंबर 2012 को एक्सेस किया गया)।

34. खान मंत्रालय, अफगानिस्तान, "अफगानिस्तान के खनन क्षेत्र में निवेश करने के 10 कारण", काबुल. http://mom.gov.af/Content/files/10%20_reasons-10pg-4.pdf (11 दिसंबर 2012 को एक्सेस किया गया)।
35. दि वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट, "वर्ल्डवाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स-2002, 2007, 2012, अफगानिस्तान", http://info.worldbank.org/governance/wgi/ index.aspx#reports (23 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
36. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, "करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2013", http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ (23 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।
37. वर्ल्ड बैंक समूह, "डूइंग बिज़नेस: मेज़रमेंट बिज़नेस रेगुलेशंस", http: //www.doing business.org/ data / expleconomies / afagonistan / (23 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
38. खान और पेट्रोलियम मंत्रालय, अफगानिस्तान, "राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संसाधन गलियारे कार्यक्रम (एनआरआरसीपी)", 2013. http://mom.gov.af/ en / page/ 6355 (11 दिसंबर, 2013 को एक्सेस किया गया)।
39. राष्ट्रपति का कार्यालय, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ अफ़गानिस्तान, "प्रेसिडेंट ग़नी कॉल्स इन चाइनीज़ कंपनीज़ टू इन्वेस्ट इन अफ़गानिस्तान", 28 अक्टूबर 2014. http://president.gov.af/en/news/37781 (5 नवंबर को एक्सेस किया गया) 2014)।
40. चंद्र, लोकेश. "अफगानिस्तान और भारत: हिस्टोरिको-कल्चरल पर्सपेक्टिव"। दि अफगानिस्तान क्राइसेस : इशुज़ एंड पर्सपेक्टिव्स. के. वारिकू द्वारा संपादित, नई दिल्ली: भवन बुक्स, 2002, पृ. 1-15.
41. हबीब, इरफान. एन एटलस ऑफ़ दि मुगल एम्पायर, दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1982. पृ. xv, 0A, 1A-B, 2A-B, शीट 1A-B, 2; शीट 1 ए-बी, 3; चंद्रा, सतीश। मध्यकालीन भारत: सल्तनत से लेकर मुगलों तक, भाग - II, नई दिल्ली: हर-आनंद प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, 1999, पृ. 217- 218.
42. रॉय-चौधरी, राहुल, "भारत." इन अफगानिस्तान टू 2015 एंड बियॉन्ड, टोबी डॉज और निकोलस रेडमैन द्वारा संपादित, 2012, लंदन: द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज, रूटलेज, 2012, पृ. 231.
43 तदेव
44. एनडीटीवी, " तालिबान थ्रेट फ्रॉम अफ-पाक रियल : एयर चीफ", 28 अप्रैल, 2012. http://www.ndtv.com/video/player/news/taliban-threat-from-af-pak-_real-air-chief/230676 (16 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
45. बिज़नेस स्टैंडर्ड, "निरुपमा राव: अवर फोकस इन अफ़गानिस्तान इज ऑन डेवलपमेंट, 28 फरवरी, 2010. http://www.business-standard. com/article/opinion/nirupama-rao-our-focus-in-afghanistan-is-on- development-110022 8000351.html (24 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।

46. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "भारत-अफगानिस्तान संबंध", अगस्त, 2012. http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/ afagonist's-aug-2012.pdf (26 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।

47. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, "राष्ट्रों के साथ समझौता ज्ञापन". http://www.panchayat.gov.in/home/-/asset_publisher/jSJjtaEw0XxM/content/memorandum- of-understanding-with-nations?_redirecthttp% 3A%2F%2F www. panchayat.gov.in%2Fhome%3Fp_p_id%3D101INSTANCEjSJjtaE w0XxM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_ mode% 3 Dview% 26 p_ p_ colid% 3 Dcolumn 3 % 26 p_ p_ col count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D21051. (29 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।

48. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "भारत-अफगानिस्तान संबंध", अगस्त, 2012.

49. भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा 218 किलोमीटर के जरंज-डेलारम सड़क का निर्माण 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से किया गया था। दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान में सड़क ईरानी सड़क नेटवर्क से चाबहार और अफगान माला सड़क नेटवर्क से जुड़ती है। इसका उद्घाटन अफगान राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री द्वारा 2009 में किया गया था और इसे अफगान अधिकारियों को सौंप दिया गया।

50. पश्चिमी हेरात प्रांत में हरि रुद नदी पर 107 मीटर ऊंचा सलमा बांध निर्माणाधीन है। यह 42 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा (14मेवा x 3) और 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई करेगा ।

51. उत्तरी ग्रिड से काबुल तक अतिरिक्त बिजली लाने के लिए पुल-ए-खुमरी से 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन।

52. डेक्कन क्रॉनिकल, "भारत सरकार अफगानिस्तान स्टेडियम के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान देती है", 9 अगस्त 2014. http://www.deccanchronicle. com/140809/world-middle-east/article/indian-government-grants- usd-1-million-afghanistan-stadium (5 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

53. टोलो न्यूज, "करजईन कंधार टू ओपन न्यू न्यूजग्रेटिकल यूनिवर्सिटी", 15 फरवरी, 2014. http://www.tolonews.com/en/afghanistan/13858- karzai-in-kandahar-to-inaugurate-agriculture-university (16 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।

54. अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास, "भारत-अफगानिस्तान: एक विकास साझेदारी", पृ. 11. http://www.mea.gov.in/Uploads/ PublicationDocs/176_india-and-afghanistan-a-development- partnership.pdf (23 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।

55. डीएनए, "अफगानिस्तान और नेपाल के छात्रों को भारत में उन्नत शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुना गया, http://www.dnaindia.com/india/ report-students-from-afghanistan-and-nepal-elated-to-get-advanced- education-in-india-2011257 (5 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

56. अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास, "भारत-अफगानिस्तान: एक विकास साझेदारी", पृ. 10.

57. डेक्कन हेराल्ड, "कमांडो को अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों में तैनात किया जाना है", 29 अगस्त, 2013. http://www.deccanherald.com/ content/354210/commandos-deployed-indian-bases-afghanistan.html) (2 सितंबर, 2013 को एक्सेस किया गया)।
58. द व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अकादमी स्मारक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा टिप्पणी, अमेरिकी सैन्य अकादमी-पश्चिम पॉइंट, पश्चिम पॉइंट, न्यूयॉर्क, 28 मई 2014. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/28/remarks-president-united-states-military-academy-commencement-ceremony (5 नवंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।
59. इंडियन एक्सप्रेस, "सुषमा स्वराज का अफगानिस्तान में आगमन; एजेंडा पर रणनीतिक संबंध", 10 सितंबर, 2014. http://indianexpress.com/ article/world/neighbours/sushma-swaraj-arrives-in-afghanistan- strategic-ties-on-the-agenda/ (16सितंबर , 2014 को एक्सेस किया गया)।
60. मिगलानी, संजीव, "इंडिया टर्न्स टू रशिया टू हेल्प सप्लाई आर्म्स टू अफगान फोर्सेस", 30 अप्रैल 2014. http://www.reuters.com/article/2014/04/30/ us-india-afghanistan-arms-idUSBREA3T0J320140430 (16 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
61. दि ब्रिक्स पोस्ट, "चीन, भारत अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं", 10 सितंबर, 2013। http://thebricspost.com/china- india-can-play-role-role-in-afaganistan/#।.VEC_bGeSwqM (17 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
62. चौधरी, डीआर, "तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ीफ़ की अधिकारिक रक्षा यात्रा, द इकोनॉमिक टाइम्स, 13 नवंबर, 2013. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-11-13/ news/44030957_1_taliban-karzai-government-mullah-abdul-salam- zaeef (17 अक्टूबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।
63. द हिंदू, "अफगानिस्तान पर अमेरिकी दबाव का विरोध करने के लिए तालिबान भारत की प्रशंसा करता है, 23 जून, 2012. http://www.thehindu.com/news/ international/taliban-praises-india-for-resisting-us-pressure-on- afghanistan/article3539512.ece (17 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
64. दीक्षित, एस, "भारत अफगान सेनाओं को प्रशिक्षित करेगा", दि हिंदू, 5 अक्टूबर, 2011. http://www.thehindu.com/news/national/india-to-train-afagan- Force / article2512682.ece (20 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।
65. द इकोनॉमिक टाइम्स, "सेल-लेड कंसोर्टियम एएफ़आईएससीओ बैग्स ओर माइनिंग राइट्स इन हाजीगक, अफगानिस्तान", 29 नवंबर, 2011, http://articles.econ omictimes.indiatimes.com/2011-11-29/ news/30454344_1_hajigak-aynak-copper-mines-ir on-ore (21 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।
66. दि इकोनॉमिक टाइम्स, "सेल, नाल्को एंड जेएसपी अमंग 6 इंडियन कंपनीज़ इन रेस फॉर अफगान माइंस", 26 अप्रैल, 2012. http://articles. Economic times.indiatimes.com/2012-04-26/news/31410262_1_ hajigak-iron-ore-deposits-shortliste d-private-players (17 दिसंबर 2012 को एक्सेस किया गया)।

67. विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
68. तेहरान टाइम्स, "ईरान, भारत, अफगानिस्तान टू स्पर ट्रेड, ट्रांजिट वाया चाबहार", 27 अगस्त, 2012. http://tehrantimes.com/economy-and- business/100905-iran-india-afghanistan-to-spur-trade-transit-via- chabahar (Accessed December 16, 2012); FARS News Agency, “India: NAM Summit in Tehran Paves Way for Global Peace”, 2012. http:// english.farsnews.com/newstext.php? nn=91 06060022 (16 दिसंबर 2012 को एक्सेस किया गया)।
69. रॉय, सुभाजीत, "भारत अफगान ड्राई फ्रूट्स आयात करने के लिए ईरान पोर्ट का उपयोग करता है", द इंडियन एक्सप्रेस, 17 सितंबर, 2013. http://www.indianexpress. com/news/ india-uses-iran-port-to-import-afghan-dry-fruits/1170088 (15 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
70. बिज़नेस स्टैंडर्ड, "अफ़गानिस्तान कीन ऑन चाबहार, एक्स्पैक्टस पैक्ट टू बे इन्क्ड सून", 20 जून, 2014. http://www.business-standard.com/ article/pti-stories/afghanistan-keen-on-chabahar-expects-pact-to-be- inked-soon-114061800791_1.html (20 जून 2014 को एक्सेस किया गया)।
71. चित्रवंशी, रुचिका, "नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ईरान के चाबहार पोर्ट के उन्नयन के लिए आह्वान करेंगे", द इकोनॉमिक टाइम्स, 16 सितंबर, 2014. http://articles.economictimes.indiatimes. com/2014-09-16/news/53983378_1_chabahar-port-port-project- india-and-afghanistan (5 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
72. द इकोनॉमिक टाइम्स, "कैबिनेट ने ईरान में चाबहार पोर्ट की स्थापना के लिए रणनीतिक निवेश की योजना को मंजूरी दी", 19 अक्टूबर, 2014. http://articles. economictimes.indiatimes.com/2014-10-19/news/55197273_1_ chabahar-port-investment-plan-kandla (20 अक्टूबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।
73. पाकिस्तान ऑब्जर्वर, " भूमि व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में", 29 जून, 2013. http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=211114 (16 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
74. बट, क़ैसर, "अफ़गान ट्रेड: न्यू ट्रांजिट ट्रेड पैक्ट कम्स इंटू इफ़ेक्ट टुडे", द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, 1 जनवरी, 2011. http://tribune. com.pk/story/97635/ afghan-trade-new-transit-trade-pact-comes-into- effect-today/ (28 जून, 2013 को एक्सेस किया गया)।
75. पाकिस्तान टुडे, "अगला पड़ाव: ताजिकिस्तान", 20 जुलाई, 2012. http: // www। pakistantoday.com.pk/ 2012/07/20 / news / profit / next-stop-tajikistan / (13 अगस्त 2012 को एक्सेस किया गया)।
76. अफगानिस्तान में दिल्ली निवेश शिखर-सम्मेलन, "भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक संबंध", http://www.dsafagan.in/pdf/India-Afaganis tan.pdf (23 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।
77. जागरण जोश, "भारत-अफगान इनोवेशन पार्टनरशिप फेयर ओपेंड इन काबुल", 4 दिसंबर, 2013. http://www.jagranjosh.com/current- affairs/ indiaafghan-innovation-

partnership-fair-opened-in-kabul- 1386160197-1 (7 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।

78. कृष्णन, अनंत, “विद आई ऑन 2014 नाटो पुलआउट, इंडिया चाइना होल्ड डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, 19 अप्रैल, 2013. http://www.thehindu. com/news/international/with-eye-on-2014-nato-pullout-india- china-hold-dialogue-on-afghanistan/article4631039.ece (7 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
79. बिजनेस स्टैंडर्ड, "टीएपीए गैस पाइपलाइन के 2017-18 तक पूरा होने की संभावना है", 3 दिसंबर, 2013. http://www.business-standard.com/article/ economy-policy/tapi-gas-pipeline-likely-to-complete-by-2017-18- 113120300844_1.html (7 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
80. अफगानिस्तान पर दिल्ली निवेश शिखर-सम्मेलन, "भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक संबंध", http://dsafagan.in/pdf/IndiaAfaganistan.pdf (23 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।
81. अनेजा, अतुल, "फ्रेंच जायंट इन फ्रे फॉर टीएपीआई प्रोजेक्ट", द हिंदू, 16 अगस्त, 2014। http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-inter national/french-giant-in-fray-for-tapi-project/article6322440.ece (15 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
82. बिजनेस स्टैंडर्ड, “टीएपीआई गैस पाइपलाइन के 2017-18 तक पूरा होने की संभावना, 3 दिसंबर, 2013. http://www.business-standard.com/article/ economy-policy/tapi-gas-pipeline-likely-to-complete-by-2017-18- 113120300844_1.html (7 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
83. अनेजा, अतुल, "फ्रेंच जायंट इन फ्रे फॉर टीएपीआई प्रोजेक्ट", द हिंदू, 16 अगस्त, 2014। http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-inter national/french-giant-in-fray-for-tapi-project/article6322440.ece (3 नवम्बर 2014 को एक्सेस किया गया)।
84. एबीसी.एज़ैड, "ईरान जॉइन्स टीएपीआई गैस पाइपलाइन टू स्टार्ट सप्लाइज टू इंडिया", http://abc.az/eng/news/81318.html (29 मई 2014 को एक्सेस किया गया)।
85. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन, "ईरान, देश विश्लेषण संक्षिप्त अवलोकन", 22 जुलाई, 2014। http://www.eia.gov/countries/country-data. cfm? fips = ir (5 दिसंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
86. भट्टा, ज़फ़र, "बांग्लादेश टीएपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने का फैसला करता है", द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, 7 जून, 2012. http://tribune.com.pk/ story/389966/onto-the-bandwagon-bangladesh-decides-to-join-tapi- gas-pipeline-project/ (10 जून 2014 को एक्सेस किया गया)।
87. रहमान, एम. अजीजुर, "बीडी अगेन वांट्स टू ज्वाइन टीएपीआई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट", द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 29 मई 2014. http: // www. thefinancialexpress-bd.com/2014/05/29/36622 (10 जून 2014 को एक्सेस किया गया)।
88. अनेजा, अतुल, "रूस चीन और भारत को उभरते ऊर्जा गठबंधन के भागीदार के रूप में देखता है", द हिंदू, 22 जून, 2014, http: //www.thehindu। com / news / national / russia-

sawks-china-india-as-Partners-of-new-energy-alliance / article6136430.ce (3 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

89. हैदर, सुहासिनी, "रूस मूट्स मेगा एनर्जी पाइपलाइन प्रोजेक्ट विथ इंडिया", द हिंदू, 21 जुलाई, 2014. http://www.thehindu.com/todays- paper/tp-national/russia-moots-mega-energy-pipeline-project-with- india/article6232177.ece (3 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

90. दीक्षित, संदीप, "भारत 1,500 किलोमीटर लंबी कज़ाख़ पाइपलाइन प्रस्तावित करता है", दि हिंदू, 27 अप्रैल, 2013. http://www.thehindu.com/news/national/ india-proposes-1500-kmlong-kazakh-pipeline/article4658613.ece (2 जून 2014 को एक्सेस किया गया)।

91. पूरा होने पर, 1,222-किलोमीटर लंबी सीएएसए-1000 ट्रांसमिशन परियोजना किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बिजली की आपूर्ति करेगी; सीएएसए वेबसाइट। "सीएएसए-1000 परियोजना का उद्देश्य प्रकृति माता का स्मार्ट उपयोग करना है"। http: //www.casa- 1000.org/MainPages/CASAAb out.php #objective (14 जून 2013 को एक्सेस किया गया)।

92. अमेरिकी राज्य विभाग, “यू.एस. CASA-1000 बिजली परियोजना के लिए वित्त पोषण में $ 15 मिलियन की घोषणा करता है”, 11 दिसंबर, 2013. http: // www। state.gov/r/pa/prs/ps/2013/218629.htm (2 जून 2014 को एक्सेस किया गया); पाकिस्तान रेडियो, यूएस ने सीएएसए-1000 प्रोजेक्ट के लिए $ 15 मिलियन की घोषणा की, 13 दिसंबर, 2013. http://www.radio.gov.pk/newsdetail-59788 (15 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।

93. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, " सीएएसए-1000: पाकिस्तान, अफगानिस्तान विद्युत पारगमन शुल्क के लिएसहमत ", 11 अक्टूबर 2014. http://tribune.com.pk/ story/774116/casa-1000-pakistan-afghanistan-agree-electricity-transit-fee/ (16 अक्टूबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

94. सुब्रमण्यन, निरुपमा, "इंडिया बैकिंग बलूच इनसर्जेंसी", द हिंदू, 26 जुलाई, 2008. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp- International / india-backing-baloch-insurgency / article1312902.ece (4 दिसंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

95. आईएएनएस, "भारत मध्य एशिया से विद्युत आयात करने की संभावना का अध्ययन कर रहा है", 7 मार्च, 2014. http://www.business-standard.com/article/ news-ians/india-studying-possibility-of-importing-power-from- central-asia-114030700354_1.html (2 जून 2014 को एक्सेस किया गया)।

96. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए अफगानिस्तान का स्थायी मिशन, "इस्तांबुल प्रक्रिया: 'हार्ट ऑफ एशिया' में स्थिरता और समृद्धि. बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और साझा क्षेत्रीय हितों के माध्यम से 'हार्ट ऑफ एशिया' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन - अल्माटी, 27 अप्रैल, 2013. http://www.afghanistan-un.org/2013/04/istanbul-process-stability- and-prosperity-in-the-heart-of-asia-through-building-confidence- and-shared-regional-interests-

heart-of-asia-ministerial-conference-/#sthash.GxNC9EGL.dpuf (7 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।

97. अहमद, खालिद, "इफ दि ईयू कुड डू इट", इंडियन एक्सप्रेस, 25 जुलाई, 2014. http://indianexpress.com/article/opinion/columns/if-the-eu- could-do-it / (23 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
98. द इंडियन एक्सप्रेस, "इंडिया इन टॉक्स टू एक्सपोर्ट नैचुरल गैस टू पाकिस्तान वाया पाइपलाइन", 26 जुलाई, 2013. http://www.indianexpress. com/ news/india-in-talks-to-export-natural-gas-to-pakistan-via-pipe line/1146773/ (11 नवंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
99. सेठ, दिलशा, "इंडो-पाक गैस प्राइसिंग सेटल्ड एज ट्रेड टॉक्स गेन ग्राउंड", द इकोनॉमिक टाइम्स, 15 सितंबर 2014.
100. अनेजा, अतुल और सिंह, माहिम प्रताप, "यूएस-ईरान न्यूक्लियर डील, कैन हेल्प रिवाइव आईपीआई प्रोजेक्ट", द हिंदू, 20 जुलाई, 2014. http://www. thehindu.com/news/national/usiran-nuclear-deal-can-help-revive-ipi-project/article6229331.ece (5 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया); अनेजा, अतुल और सिंह, माहिम प्रताप, "पाइपलाइन टू पाकिस्तान मे रिवाइव स्टाल्ड मेगा प्रोजेक्ट्स", द हिंदू, 20 जुलाई, 2014. http://www.thehindu. com/news/national/pipeline-to-pakistan-may-revive-stalled-mega- projects/article6229237.ece (5 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
101. बीबीसी, "पाकिस्तान फ्रीज़ तालिबान लीडर अब्दुल गनी बरादर", 21 सितंबर, 2013. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24185441 (5 अक्टूबर 2013 को एक्सेस किया)।
102. बीबीसी, "पाकिस्तान पीएम शरीफ ने अफगान तालिबान वार्ता के लिए सहायता की प्रतिज्ञा की", 30 नवंबर, 2013. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25163071 (15 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
103. द हिंदू, "भारत, पाक वांट ए स्टेबल, सिक्योर अफगानिस्तान: यूएस", 4 दिसंबर, 2013. http://www.thehindu.com/news/international/ world/india-pak-want-a-stable-secure-afghanistan-us/article5420582. ece (7 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।
104. कोझेवनिकोव, रोमन, "अफ़गान नेबर ताजिकिस्तान रेटिफाइज़ बेस डील विथ रशिया", रायटर, 1 अक्टूबर, 2013। http://www.reuters.com/ article/2013/10/01/us-tajikistan-russia-idUSBRE9900CZ20131001 (5 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
105. संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास, ताजिकिस्तान, “यू.एस. दूतावास ताजिकिस्तान के सीमा-शुल्क सेवा के लिए व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र सुविधा प्रदान करता है”, 21 जनवरी 2014. http://dushanbe.usembassy.gov/pr_01212014.html (5 नवंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।
106. बीबीसी, "अफगान रेलवेज़: फर्स्ट ट्रेन रन्स ऑन न्यू लाइन इन नॉर्थ", 21 दिसंबर, 2011. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16287929 (23 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया)।

107. मैकडरमोट, रोजर एन, "सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी पोस्ट - 2014: कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान में परिप्रेक्ष्य", डीआईआईएस रिपोर्ट 2013: http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Reports2013/RP2013-12-McDermott- Kazakhstan_web.jpg.pdf (5 जून 2014 को एक्सेस किया गया)।

108. "तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान में बिजली की आपूर्ति बढ़ाएगा", 14 दिसंबर, 2013. http://www.turkmenistan.ru/en/articles/17530.html (19 दिसंबर 2013 को एक्सेस किया गया)।

109. कलिखानोवा, गुलनाज, "कजाकिस्तान कंटिन्यूज ट्रांजिट कोऑपरेशन टू स्टेब्लाइज़ अफगानिस्तान", (वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया). http://www.astanatimes. kz /index. php?uin=1290951446&pg=1369885653 (22 अक्टूबर 2013 को एक्सेस किया गया) ।

लेखकों के बारे में

डॉ. दिनोज के उपाध्याय, रिसर्च फेलो, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

डॉ. अथर ज़फर, रिसर्च फेलो, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली- 110 001

ISBN 978-93-83445-06-6
9 789383 445066